मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक

वर्ष: 43 अंक: 18 नई दिल्ली (कुल पेज 16) 30 अप्रैल – 6 मई 2023 मूल्य 7 रुपये

अंदर के पेजों में

उत्पीड़ित दुनिया में मजदूरों की मांगें.....3

भाकपा के जन अभियान को मिल रहा है व्यापक जन समर्थन.....7

वर्तमान समय में मजदूर वर्ग के समक्ष चुनौतियां.....8–9

जोर–शोर से मई दिवस मनाने का आह्वान

लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ

अमरजीत कौर

2023 के मई दिवस को मजदूर वर्ग ज्यादा जोश के साथ कई कारणों से मनाएगा। 2024 में होने वाले चुनावों से पूर्व प्रत्येक मोर्चे पर बहुत तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए यह बहुत जरूरी है कि इस राजनीतिक स्थिति का आकलन किया जाए।

सभी अनिवार्य वस्तुओं के दाम–जैसे कि अनाजों, दालों, आटा, खाद्य तेल, रसोई गैस के (एक सिलिंडर का दाम लगभग 1200 रु. हो गया है), दूध के खुदरा दाम में पिछले एक साल में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी, शिक्षा और स्वास्थ्य उपचार में बढ़ते शुल्क के साथ–साथ अर्थव्यवस्था में और गिरावट से सभी अनिवार्य वस्तुएं आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं क्योंकि आम आदमी की आय/वेतन नहीं बढ़ रही है।

लोकसभा के आम चुनावों से पूर्व मोदी नीत भाजपा सरकार का पिछला पूरा बजट दिखाता है कि सरकार लगातार कॉरपोरेट परस्त नीतियों को मजदूरों, किसानों और आमतौर पर गरीब असुरक्षित वर्ग की कीमत पर आगे बढ़ा रही है। बजट दिखाता है कि कॉरपोरेटों को अधिक रियायतें मिल रही हैं जबकि शिक्षा, जन–सुविधाओं के बजट, एससी/एसटी सब–प्लान में कटौती हुई है। साथ ही मनरेगा आवंटन में 30 प्रतिशत की कटौती की गई है, इसी तरह अन्य सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं में की गई कटौतियां साफ दिखती हैं।

वित्त मंत्री का बजट भाषण झूठ से भरा हुआ था। जिन अनुमानों को उपलब्धियों के रूप में पेश किया गया थ वे जमीनी हकीकत से बहुत दूर थे।

समावेशी विकास, दूरस्थ व्यक्ति तक पहुंचना, युवा शक्ति आदि जैसी बजट में सूचीबद्ध सातों प्रमुख प्राथमिकताएं बिना किसी सच्चाई के खोखली थी। मजदूर वर्ग के सरोकारों से संबंधित कोई भी वास्तविक मुद्दा जैसे कि पुरानी पेंशन स्कीम, सभी को सामाजिक सुरक्षा, स्कीम वर्कर्स का नियमितीकरण, असंगठित एवं खेत मजदूरों को न्यूनतम वेतन, केंद्र और राज्य में खाली पड़ी नौकरियों का भरना आदि को संबोधित किया गया। इस बजट में देश के हित को पीछे छोड़ दिया गया है और साथ ही देश के सकल घरेलू उत्पाद में 60 प्रतिशत का योगदान करने वाले 94 प्रतिशत असंगठित श्रम बल के हित को भी पीछे छोड़ दिया गया है।

मजदूरों के साथ इंसानों के जैसा व्यवहार हो जानवरों के जैसा नहीं को दावे के साथ कहने के लिए मई दिवस हमें मजदूरों और उनकी यूनियनों के उस विशाल बलिदान की याद दिलाता है।

बल्कि कोई यह दावा कर सकता है कि मानव इतिहास में मानव अधिकारों की विमर्श मजदूर आंदोलन से शुरू हुई थी। उनकी काम के घंटों को निर्धारित करने के मांग – काम के लिए 8 घंटे, आराम के लिए 8 घंटे, और परिवार के साथ मनोरंजन और स्फूर्ति के लिए 8 घंटे – 19 वीं शताब्दी में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में गूंज गई थी।

भारत में भी काम के निर्धारित समय की मांग 1866 से शुरू हुई थी, तब यूनियनों का क्षेत्रवार जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि तब तक सामूहिक मुद्दों के लिए समूहबद्ध होने का आधार सामुदायिक था। 1886 में यह पहली मई थी कि शिकागो में मजदूरों ने 1 मई को अपनी विरोध हड़ताल शुरू की, इसके बाद इसके बाद इस आंदोलन को कुचलने का कारण बनाने के लिए साजिशकर्ताओं द्वारा बम विस्फोट किया गया। आठ नेताओं को गिरफ्तार किया गया, उनमें से चार को मौत की सजा दी गई, दो की जेल में मृत्यु हो गई और दो को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

1889 में कामगार संघों की एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक में कार्ल मार्क्स ने मजदूर वर्ग की मांगों की बात की, शिकागो में मई प्रदर्शन की घटनाओं की चर्चा की और उस संघर्ष के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मई दिवस मनाने का और काम के घंटों को निर्धारित करने के लिए संघर्ष को जारी रखने का सुझाव दिया । 1890 से इस दिन को "दुनिया के मजदूरों एक हो" के नारे के साथ मनाया जाना शुरू हुआ।

संघर्ष जारी रहा और 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ (आईएलओ) के अपने स्थापना का पहला सम्मेलन आठ घंटे के कार्य दिवस से किया। भारत में ऐटक की एक यूनियन ने 1920 में पहली बार तमिलनाडु में मई दिवस मनाया था। आज हम एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जब कढ़े संघर्ष से मिले श्रमिक अधिकार 150 सालों के बाद श्रमिक विरोधी नीतियों और श्रमिक कानूनों के संहिताकरण से खतरे में हैं।

बजट में दीर्घ अवधि रोजगार और गुणवत्तापूर्ण रोजगार निर्माण को संबोधित नहीं किया गया। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा 34 प्रतिशत पर है। बजट में मांग आधारित कौशल की बात कही गई। कौशल आता है औपचारिक शिक्षा से। भारत में औपचारिक शिक्षा की वास्तविकता पर ध्यान दिए बिना कौशल विकास का कोई औचित्य नहीं बनता।

इन्डस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखते हुए नव युग पाठ्यक्रम प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित लघुसंख्य युवाओं के लिए है। बजट में उच्च शिक्षा पर खर्च की बात की गई है वास्तव में यह विदेशी विश्वविद्यालयों को लाने की योजना है। भाजपा अभी तक शिक्षा पर केवल सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से कम आवंटित कर रही है।

स्वास्थ्य पर कटौती ने भारत में गरीबी को बढ़ाया है। कृषि बजट को घटाकर किसानों के दिए जाने वाले अंशदान के बराबर करना चुनावी पैंतरेबाजी है।

महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक में डिपोजिट सीमा के बढ़ाने से कोई बड़ा भला नहीं होगा। महिलाओं के वेतन में बढ़ती विषमता और घटते महिला रोजगार को संबोधित नहीं किया गया।

चुनिंदा वस्तुओं पर जीएसटी ने ग़ैर–जरूरी वस्तुओं के दाम घटाएं हैं। इससे आम आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ है जो कि अप्रत्यक्ष कर अदा करता है।

मध्यम लघु और सूक्ष्म उद्योगों (एमएसएमई) को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया है। एमएसएमई जो कि विकास का ईंजन है और रोजगार पैदा करता है उसे गारंटी बढ़ाने के नाम से जो दिया है वह इस क्षेत्र के उद्योगों की विशाल संख्या के हिसाब से बहुत कम है।

बजट खामोश रहा यह बताने के लिए कि राजस्व कहां से कमाया गया। अमीरों और कॉरपोरेटों पर कर लगाने के माध्यम से कर आय को बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं की गई। घाटे को पूरा करने के लिए लिया गया कर्ज साफ दिखता है। भारत का कर्ज का बोझ पहले ही बहुत ज्यादा है और ज्यादा कर्ज बोझ से ब्याज का भार बढ़ जाएगा।

बजट ने न केवल आम आदमी की आकांशओं को ठुकराया है बल्कि यह बजट संसद में बिना किसी बहस के हुआ है। यहां तक की बजट पूर्व मंत्राणाओं को मजाक बना दिया गया और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने इसका विरोध किया। वित्त मंत्री ने इस बजट को ''अमृत काल'' बजट कहा जो कि सरकार का असली चेहरा है।

देश में बढ़ती बेरोजगारी की स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। रोजगार छंटनी और तालाबंदी की खबरें रोज़ न केवल औद्योगिक क्षेत्र से मिल रही हैं बल्कि आईटी क्षेत्र से भी, जहां उच्च शिक्षित युवा रोजगार में हैं।

हिन्डनबर्ग की रिपोर्ट आने से अडानी का साम्राज्य गिर रहा है,

शेष पेज 15 पर...

कामरेड लेनिन को याद किया गया

भाकपा के केन्द्रीय मुख्यालय अजय भवन में 22 अप्रैल 2023 को कामरेड वी आई लेनिन की 153वीं जयंती मनाई गई। भाकपा महासचिव डी राजा ने कहा कि अमीर और शक्तिशाली द्वारा मानव का शोषण समाप्त करने के लिए हमें अपने संघर्षो को तेज करना चाहिए।

कॉमरेड लेनिन की लगातार बढ़ती प्रासंगिकता

आज जब हम अपने नेता और दार्शनिक कॉमरेड वी.आई. लेनिन की जन्मशती अप्रैल 22 को मना रहे हैं, ऐसे समय में, जिस वित्त पूंजी को उन्होंने परिभाषा दी थी, उसी के वर्चस्व में हम सब जी रहे हैं। वित्त पूंजी के लिये लेनिन ने कहा था कि यह पूंजीवाद का उच्चतम स्वरूप है, जिसमें हमारे जनवादी अधिकार, हमारा संविधान, अपनी सरकार चुनने का हमारा अधिकार और जीने और सोचने की हमारी सारी विविधता को खत्म कर दिया जाता है। यह हमें खाना देने से मना करता है, और उसके बदले काफी व्यवस्थित अकाल परोसता है। यह हमें जीविका देने से भी मना करता है, क्योंकि इसकी प्रमुख दिलचस्पियों की सूची में निवेश नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा इसकी प्राथमिकता नहीं है। लोक कल्याण की निष्ठुर उपेक्षा की जाती है, लेकिन इस सबके साथ यह भी सच है कि यह जनता का सामना करने से कतराता है, उसकी असीम शक्ति से भी डरता है। यही वह परिस्थिति है जिसके लिये कभी कॉमरेड लेनिन ने सारी जनवादी ताकतों को एकजुट होने पर जोर दिया था, और जिसमें ग़ैर–इजारेदार पूंजीपति भी शामिल थे। यह एकता एक जनवादी राष्ट्र के लिये थी, और आज भी है। केंद्र में सरकार को यह अहसास है कि जनवाद के नाम पर कुछ करने की अनिवार्य आवश्यकता है, जिसमें चुनाव तो करवाए जायंगे, लेकिन किसी आंदोलन की अनुमति नही होगी, और उसे कारण के साथ बताने की भी आवश्यकता महसूस नहीं करेगा शासक पक्ष। विरोधी पक्ष को अपनी जनवादी भूमिका निभाने की आजादी नहीं होगी और न ही संसदात्मक जनवाद के अनुसार, कोई निर्णय ले़ने की अनुमति होगी। सरकार के लिये किसी भी निर्णय को पारित करने के लिये खुला मैदान होगा, निषेध के बिना।

वित्त पूंजी की परिभाषा के क्रम में लेनिन के अनुसार यह वित्तपूंजी दक्षिणपंथी विचारों के सहयोग से, अंधराष्ट्रवाद के लिये जगह तैय्यार करता है। इसी को साबित करने के लिये, दशकों पहले, दक्षिणपंथी विचारों के नायक वी.डी. सावरकर, अपने अंधराष्ट्रवाद की परिभाषा में, 1923 में अपनी किताब में लिखते हैं, ''सभी हिन्दू यह कहते हैं कि उनकी नसों में शक्तिशाली वीरों का रक्त बहता है, जो उनके वैदिक पिताओं से विरासत में उन्हें मिला है।'' वे फिर लिखते हैं, ''हम (हिन्दू) आज एक हैं, क्योंकि हम सभी एक ही राष्ट्र से हैं, एक ही जाति और एक ही संस्कृति हमें मिली है।''

इसलिये आज यह एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है कि हम सब एकजुट होकर जो भी अवसर प्राप्त हों, उनमें आंदोलन करें एकजुट होकर, अपने जनवादी अधिकारों के लिये, चुनाव के लिये, संसदात्मक लोकतंत्र के लिये। लेनिन ने कहा था कि कम्युनिस्टों को चुनाव में हिस्सा जरूर लेना चाहिए किसी भी लोकतंत्र की तरह, और इस पर जोर दिया कि सभी जनवादी ताकतों को एक होकर सक्रिय होना है। किसान आंदोलन लगातार होना चाहिये और इसके लिये संयुक्त मोर्चा भी इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये चलाना चाहिये।

निस्संदेह कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन पूंजीवादी जनवादी होता है, लेनिन ने कहा और आगे इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि

संपादकीय

संयुक्त मोर्चे की मांग आज का समय कर रहा हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपने इस लेनिनवादी नतीजे पर पहुंच चुकी है। संयुक्त मोर्चे में पूंजीपति वर्ग का साथ एक ऐसी भविष्यवाणी की तरह उल्लिखित हुआ जिसका महत्व आज भी औचित्य लिये खड़ा है। यह ज्यार्जी दिमित्रोव ही थे जिन्होंने इस विचार को विकसित किया और साम्राज्यवाद जो एक वास्तविक शक्ति के रूप में बदलता जा रहा था उसका सामना करने के लिये उपयुक्त प्रस्तुति भी ली। यह 1935 का समय था जब साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चा एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुका था।

कॉमिन्टर्न की सातवीं कांग्रेस को संबोधित करते हुए दिमित्रोव ने कहा, '' ....अपनी राजनैतिक और सांगठनिक स्वतंत्रता को कायम रखते हुए उन्हें कांग्रेस के कार्यक्रमों में हिस्सा लेना होगा, ब्रिटिश साम्राज्यवाद से संघर्ष करने के लिये एक राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन की तैय्यारी करनी होगी जिसमें समस्त जनता साथ होगी, और इसका दायित्व होगा राष्ट्रीय क्रांतिकारी शाखा पर, जो संयुक्त मोर्चे का होगा।'' संयुक्त मोर्चे के इस विचार को दिमित्रोव द्वारा ठोस रूप देने से बहुत पहले ही लेनिन को इसका पूर्वाभास हो चुका था। उन्हें मालूम था कि साम्राज्यवाद का आना अनिवार्य है। उन्होंने इसे समाजवाद के लिये एक विशाल पृष्ठभूमि के रूप में लिया और इसे स्वरूप देने के क्रम में उन्होंने इसका विकास करते हुए कहा कि मज़दूर वर्ग इस संक्रमण में जरूर दिलचस्पी लेगा।

आज जितनी मांगें पूंजीवादी जनवाद के दिनों में उठाए जा रहे हैं वे सभी मज़दूर वर्ग के लिये ही हैं। जीविका के अवसरों की मांग मजदूरों की है, पर इसमें पूंजीपति के भी औद्योगिक विकास का प्रश्न जुड़ जाता है। कृषि क्षेत्र में भी एम.एस.पी. की मांग भी उनके ही हित का समाधान करती है। जनवाद और संसदात्मक संस्थाओं की परिधि आज अत्यंत विस्तृत हो चुकी है। पूंजीवाद के लिये जनवाद की स्थापना उसके अपने अस्तित्व के प्रश्न को हल करता है। इसलिये आज जरूरत है व्यापक बुनियाद पर साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष की। हमारे देश में यह संघर्ष अपने संविधान को बचाने के लिये होगा, जिससे हमारी जनवादी व्यवस्था मज़बूत होगीं इसलिये कॉमरेड लेनिन का अवदान आज हमारे लिये अत्यधिक प्रासंगिक है। कोई भी आंदोलन आज पूंजीवादी जनवादी सार के साथ ही शुरू होता है।

आज जितनी भी मांगें उठ रही हैं, वे सभी एक जनवादी आंदोलन का हिस्सा तो हैं ही, साथ ही वे पूंजीवादी जनवादी भी हैं। इसका कारण है इजारेदारों के विकास में ग़ैरइजारेदार हिस्सा बाधक होता है, इसलिये उसे ख़त्म करने की केशिश होती है। छोटे और मझोले उद्योगपति कुचल दिये जाते हैं। इसलिये ग़ैरइजारेदार तबके का यह वर्गीय विरोध है कि पूंजीवाद को इजारेदारी में बदलने से रोका जाय। इस तरह जनवादी आंदोलन का सार ही है साम्राज्यवाद का विरोध। यहां आता है डायलेक्टिक्स या द्वन्द्ववाद। इसमें मज़दूर वर्ग और पूंजीवादी वर्ग का स्वार्थ एक हो जाता है। ऐतिहासिक विचारों के विकास के क्रम में एक स्थिति आती है जब मज़दूर वर्ग जनवादी उद्देश्यों का सबसे बड़ा और सशक्त रक्षक बन जाता है, और साथ ही पूंजीवाद के लिये भी।

लेनिन के निर्देशों पर चलते हुए दिमित्रोव ने ज़ोर देकर कहा कि कम्युनिस्टों को सभी साम्राज्यवाद विरोधी ताक़तों के साथ मिलकर काम करना है, उन्हें भी साथ लेना है जिन्हें सुधारवादी माना जाता है। इन सबके साथ अपनी राजनैतिक और सांगठनिक स्वतंत्रता को भी बचाकर रखना है।

महिला फेडरेशन का चैंपियन पहलवानों के पक्ष में प्रदर्शन

नई दिल्ली, 25 अप्रैल 2023: जैसा कि दिल्ली पुलिस आयुक्त ने नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमन (एनएफआईडब्ल्यू) के एक प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया, उन्होंने आज मध्य दिल्ली के जय सिंह रोड स्थित दिल्ली पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) पर विरोध प्रदर्शन किया। युवा महिला पहलवानों द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर एनएफआईडब्ल्यू सदस्य पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपने के लिए पीएचक्यू गए।

प्रदर्शन का नेतृत्व एनएफआईडब्ल्यू महासचिव एन्नी राजा ने किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया और संसद मार्ग थाने ले जया गया। थाने में पुलिस उपायुक्त आयुक्त की तरफ से ज्ञापन प्राप्त किया। उसके बाद प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई।

ज्ञापन में एनएफआईडब्ल्यू ने पुलिस आयुक्त से पहलवानों को अपराधिक धमकी और महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज करने और गिरफ्तार करके जेल भेजने की मांग की गयी है।

ज्ञापन में महिला फेडरेशन की निम्न मांगें हैं:

–खिलाड़ियों के द्वारा की गयी शिकायतों के आधार पर बृजभूषण शरन सिंह के खिलाफ तुरंत केस दर्ज। यह केस कार्यस्थल पर उत्पीड़न और पोक्सो के तहत दर्ज हों।

–शिकायतकर्ताओं को न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक समयबद्ध कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए।

–शिकायतों पर समय पर एफआईआर दर्ज नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए।

–महिला और बच्चों से संबंधित कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए दिल्ली पुलिस के लिए तुरंत लैंगिक संवेदनशीलता और जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए।

सोनभद्र में बीकेएमयू राज्य सम्मेलन की तैयारियां

ओबरा (सोनभद्र), 9 अप्रैल 2023: उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन के 14वें राज्य सम्मेलन की तैयारी हेतु उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ कार्यालय ओबरा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिला ट्रेड यूनियन, बिजली कर्मचारी संघ, खेत मजदूर यूनियन की संयुक्त बैठक सी पी माली, लालता प्रसाद तिवारी, रामबदन यादव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में एटक के वरिष्ठ नेता लल्लन राय उपस्थित रहे, संचालन खेत मजदूर यूनियन के प्रान्तीय सचिव डाक्टर आर के शर्मा ने किया! बैठक को सम्बोधित उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन के महामंत्री फूलचन्द यादव ने किया और राज्य सम्मेलन की तैयारियों का जायजा भी लिया।

फूलचन्द ने अपने संबोधन में मौजूदा मोदी और योगी सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए इन नीतियों को मजदूर विरोधी खासतौर पर खेत मजदूर विरोधी बताया। उन्होंने आगामी राज्य सम्मेलन में आरएसएस–भाजपा सरकार की नीतियों के विरोध के लिए एक व्यापक और एकताबद्ध संघर्ष पर जोर दिया। उन्होंने मौजूद साथियों से इस सम्मेलन को कामयाब बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ने और पूरी लगन से इसे कामयाब बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया।

मई दिवस–2023

उत्पीड़ित दुनिया में मजदूरों की मांगें

श्रीनिवास खाण्डेवाले

सभी मामलों में, आर्थिक दुनिया आज एक उत्पीड़ित दुनिया है, विशेष रूप से मेहनतकश जनता की दुनिया। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्रम के लिए उत्पीड़ित संसार कब नहीं था? हम 'टुडे मोर सो' जोड़ेंगे। विकास के प्रत्येक चरण में, श्रम को उत्पीड़ित किया गया और इसने हमेशा बेहतर की मांग के लिए आवाज उठाई। हर बार एक बेहतर डील का वादा किया गया लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ और फिर श्रम को अगली अवधि में धकेल दिया गया।

औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के साथ, एक आशा दी गई थी कि दुनिया के मजदूरों को आराम से जीवन यापन मिले। लगभग 1750 से शुरू होकर, मजदूरों को भूखा और क्षीण बनाए रखते हुए, औद्योगिक लाभ में कई गुना वृद्धि हुई, महिलाओं और बच्चों को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शोषण का अधिक से अधिक सामना करना पड़ा।

द्वितीय विश्व युद्ध (1945 में) के बाद, गुलामी झेल रहे लोगों द्वारा साम्राज्यों को नष्ट कर दिया गया था, अब उपनिवेश संप्रभु देश बन गए थे। लेकिन गरीबी और सामान्य विरासत में मिले पिछड़ेपन के दबाव में नव स्वतंत्र देशों को विकसित देशों के वित्तीय और तकनीकी नेतृत्व में बने रहना पड़ा। फिर भी 1945 और 1980 के दशक के बीच, विकासशील देशों ने विकसित देशों से अलग स्वायत्त व्यवहार और विकास के मॉडल पेश किये। इसके परिणामस्वरूप विकसित देशों का अंतर्राष्ट्रीय लाभ कम हुआ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, एक प्रस्तावित बहुपक्षीय संगठन को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस डर से बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया गया था कि यह उसकी आंतरिक आर्थिक नीतियों में हस्तक्षेप कर सकता है।

टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता (जीएटीटी), एक समझौता जो पहले सबसे अमीर जी –7 देशों के बीच संपन्न हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता रहा। मुक्त व्यापार स्थापित करने के लिए सात दौर के बाद, 1994 में 8वें दौर में, एक बहुपक्षीय व्यापार संगठन (विश्व व्यापार संगठन = डब्ल्यूटीओ) का गठन किया गया और 1995 में संचालन किया गया। इस अवधि को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी एलपीजी के रूप में जाना जाता था। इसने लोगों को पूर्ण रोजगार और बेहतर जीवन स्तर का वादा किया था, लेकिन आश्वासनों पर अमल नहीं हुआ। क्रमिक विकास में, दुनिया सामान्य रूप से और विशेष रूप से मजदूर, मंदी (2008, 2015 से 2020 तक), बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, आय और धन असमानताओं आदि से पीड़ित थे और अभी भी पीड़ित हैं। और अब, 2023 में, विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट आई है: 'फॉलिंग लॉन्ग–टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स' के एक दशक लंबे प्रोजेक्शन पर (एडवांस एडिशन, कोस, एम. अहान और ओह्वसॉर्ग, फ्रांजिस्का, एडस 2023 फॉलिंग लॉन्ग–टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स: ट्रेंड्स, एक्सपेक्टेशंस एंड पॉलिसीज, वाशिंगटन, डीसी: विश्व बैंक लाइसेंस: 3.0 आईजीओ द्वारा क्रिएटिव कॉमन्स एट्रिब्यूशन सीसी)।

वृद्धि में गिरावट और मजदूरों का भविष्य

विश्व बैंक की रिसर्च से जाहिर होता है कि 21वीं सदी की शुरुआत में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत थी; यह 2021–23 के दौरान 2.6 प्रतिशत तक गिर गयी है और 2030 तक इसके 2.2 प्रतिशत तक गिरने का अनुमान है।

अपनी ओर से, विश्व बैंक की रिपोर्ट ने अकेले निजी क्षेत्र के माध्यम से विकास को ध्यान में रखते हुए, अपने सदस्य देशों को छह नीतिगत सुझाव दिए हैं, यथा (1) निवेश दरों में वृद्धि (2) राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों को संरेखित करना (3) लॉजिस्टिक्स में सुधार, विनियमन और व्यापार लागत में कटौती (4) डिजिटल डिलीवरी सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अधिक शिक्षा और कौशल (5) श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, और (6) अधिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग, जो सोवियत संघ के टूटने के बाद 1990 के दशक में उच्च था, और बाद में लड़खड़ा गया।

इन नीतिगत सुझावों पर एक नजर डालने से पता चलेगा कि सुझाव आपूर्ति–पक्ष उन्मुख हैं और रोजगार, सुनिश्चित उच्च आय, कम आय और धन असमानता आदि के बारे में कोई संकेत नहीं देते हैं, जिसका सामना जनता कर रही थी और कर रही है।

भारतीय मई दिवस की मांगें

भारत में कई विशिष्ट समस्याएं हैं और लंबी अवधि के धीमे विकास को देखते हुए लेबर की विभिन्न आर्थिक मांगों पर विचार करना होगा:

(ए) सबसे अधिक आबादी वाला देश: संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट (दिनांक 19–04–2023) के अनुसार, 2023 के मध्य तक भारत 142.86 करोड़ जनसंख्या के साथ सबसे अधिक आबादी वाला देश होगा, जिसके बाद 142.57 करोड के साथ चीन का दूसरा स्थान होगा। भारत में 15–64 वर्ष आयु वर्ग की 68 प्रतिशत आबादी है।

सितंबर 2022 में जारी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत मानव विकास सूचकांक में 2020 में 130वें स्थान से फिसलकर 2021 में 132वें स्थान पर आ गया है। सभी देशों में स्थिति कठिन रही है, यह कोई कोई सांत्वना की बात नहीं है क्योंकि फिर भी लगभग 130 देश (191 देशों में से) भारत से उपर हैं।

मांगें

हम भारत में मजदूर वर्ग के लिए जरूरी नीतिगत अनिवार्यताओं के दृष्टिकोण से मांगों को नीचे दे रहे हैं:

1. गैर जरूरी निजीकरण को रोकना और सार्वजनिक क्षेत्र को संरक्षित करना

रोजगार के रखरखाव और जन कल्याण के प्रति निजी क्षेत्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसका घोषित उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में दीर्घकालिक गिरावट की संभावनाओं के सामने, उत्पादन और रोजगार की स्थिरता, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम विशाल कामकाजी आबादी के लिए बेहतर समर्थन हैं।

इसलिए विनिवेश को ना कहें।

2. घरेलू मांग को प्रोत्साहित और उसे बचाना

वैश्विक विकास की दीर्घकालिक अपेक्षाओं में गिरावट और निर्यात की घटती संभावनाओं को देखते हुए, घरेलू मांग की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। चीन पहले ही घरेलू मांग की ओर ध्यान केंद्रित कर चुका है। कई अन्य देशों की तुलना में भारत के पास एक विशाल आंतरिक बाजार का लाभ है।

3. ग्रामीण आवास का योजनाबद्ध पुनर्निमाण

ग्रामीण भारत में घर बहुत पुराने, खराब नियोजित, खराब हवादार, कई आवश्यक सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। गांवों को आधुनिक योजना की जरूरत है। घरों के चरणबद्ध पूर्ण पुनर्निर्माण के लिए अकुशल और कुशल श्रमिकों, वास्तुकारों और इंजीनियरों की सभी निर्माण सामग्री और सेवाओं की आवश्यकता होगी। राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच ऐसी परियोजना के वित्तीय व्यय को साझा करने के लिए वित्त आयोग के स्तर पर वित्तीय आवंटन में उचित संशोधन की आवश्यकता होगी। लेकिन यह सार्थक होगा क्योंकि इससे ग्रामीण संपत्ति का सृजन होगा; ग्रामीण जीवन का आधुनिकीकरण; दशक के दौरान विश्व स्तर पर गिरती जीडीपी विकास दर के समय प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा।

4. अत्यधिक शहरी औद्योगिक केन्द्रीकरण को हतोत्साहित करना

स्वतंत्रता के बाद की अवधि के दौरान सामान्य रूप से और विशेष रूप से वैश्वीकरण के बाद, शहरी केन्द्रीकरण को बढ़ावा दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप महानगरों का दम घुट रहा है। फिर भी, महानगरीय क्षेत्रों में आसपास के गाँवों को शामिल करके महानगरीय क्षेत्रों (महाराष्ट्र की तरह) का गठन; दूर–दराज स्थित क्षेत्रों से भी पलायन में वृद्धि और विस्तारित महानगरीय क्षेत्र में प्रवासित आबादी को समायोजित करना शहरी क्षेत्रों के विकास का एक मानक पैटर्न बन गया है। इसे कभी तो रोकना होगा। संभवत: यह बड़े शहरों की भीड़भाड़ कम करने और विकास को ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाने का उपयुक्त समय है। बाजार की ताकतें निश्चित रूप से इसका विरोध करेंगी। इसका तात्पर्य है कि एक सरकार के पास एक नई दृष्टि और संकल्प होना चाहिए।

ग्रामीण औद्योगीकरण की नए सिरे से योजना बनाने की जरूरत है। आज, दूरस्थ तालुका स्थानों में इंजीनियरिंग और एमबीए के छात्रों को शहरी औद्योगिक निगमों का हिस्सा बनने के नजरियो से प्रेरित किया जाता है। हाल ही में एक महानगरीय आईआईटी के एक प्रोफेसर ने तर्क दिया है (और सही भी है) कि आईआईटी के शिक्षकों और छात्रों को आसपास के क्षेत्रों में लोगों के पास जाना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। किन्तु वर्तमान में न तो महानगर और न ही देश के तकनीकी संस्थान आसपास के लोगों तक जा सकेंगे ! दोष शिक्षकों और छात्रों का नहीं, बल्कि शिक्षा के कारपोरेट पूंजीवादी मॉडल का है। अब, यदि विकास का वैश्विक पूंजीवादी मॉडल बार बार होने वाली मंदी से पीड़ित है, तो क्या पूंजीवादी विकास का भारतीय मॉडल उपयुक्त रूप से बदला जाएगा? यदि उपरोक्त विश्व बैंक प्रतिवेदन की आलोचनात्मक समीक्षा नहीं की जाती है, तो इसका अर्थ होगा कि उद्देश्यों, दृष्टि, मॉडल, संस्थानों और शासन की शैलियों के संबंध में, यह कहानी हर दशक में दोहराई जाती रहने वाली है! ये सभी आवश्यक परिवर्तन मूल रूप से श्रमिकों और नागरिकों द्वारा सही प्रकार की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पर जोर देने से ही होंगे।

5. जलवायु परिवर्तन: तात्कालिक चुनौतियां

इस खुशी देने वाली राय के अलावा कि भारत (विशेष रूप से कृषि क्षेत्र) जलवायु परिवर्तन से भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होने जा रहा है, यह एक सच्चाई है कि असमय, बेमौसम बारिश विभिन्न क्षेत्रों में खरीप, रबी या बागवानी फसलों को खराब कर रही है और प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है (1) एक ओर समाज के लिए उपलब्ध कृषि सामग्री, और (2) दूसरी किसानों को बेचे जाने वाले उत्पादों की मात्रा और उनसे होने वाली आय।

जलवायु परिवर्तन की मात्रा और उसके परिणामों के अलावा, आइए हम इसके मूल कारण के बारे में पूछें। यह लक्षित और प्रयास करके हासिल वृद्धि की अतिशयोक्तिपूर्ण दर है; राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के बीच अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और प्रदूषण के कारण ईंधन का अंधाधुंध उपयोग (अब भी जारी है)। जलवायु परिवर्तन से लड़ने को हर घर, समुदाय और संस्था को इस संस्कृति का हिस्सा बनाने की जरूरत है।

6. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करो का सही मिश्रण

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में आय वितरण संरचना लगभग नब्बे प्रतिशत आबादी को दरकिनार कर रही है, जिससे 10 प्रतिशत ऊपरी आबादी को अनुपातहीन रूप से लाभ मिल रहा है। क्या राष्ट्रीय आय का ऐसा असमान वितरण दीर्घकालीन मंदी की स्थिति में लोगों को जीवित रहने में मदद कर सकता है? हरगिज नहीं। भारी अप्रत्यक्ष (जीएसटी) कराधान और कम प्रत्यक्ष कराधान कम आय वाले लोगों के लिए कठिनाई पैदा कर रहा है। सरकार द्वारा कर ढांचे को फिर से डिजाइन करने के लिए अत्यंत सावधानी बरतनी होगी ताकि निम्न और मध्यम आय वाले लोगों को वित्तीय राहत दी जा सके और उन्हें 'गिरती दीर्घकालिक विकास संभावनाओं' का सामना करने में सक्षम बनाया जा सके। नीतियां लोगों के लिए होती हैं न कि इसके विपरीत!

उलझन

बार बार होने वाली मंदी की प्रवृत्ति से बचने और उसे ठीक करने के लिए लगभग सभी नीतिगत विकल्पों की कोशिश करने के बाद, नीति और संस्थागत विफलता और भविष्य में क्या किया जा सकता है, इस बारे में उलझन की भावना है। एक राय है कि कुछ लीक से हटकर सोचना चाहिए। कुछ अन्य लोगों की राय है कि कोरोना के बाद दुनिया बदल गई है और एक नया अर्थशास्त्र ईजाद किया जाना चाहिए। हम, अपनी ओर से, इस तरह के विचारों से आंशिक रूप से सहमत हो सकते हैं और यह जोड़ सकते हैं कि, 21वीं सदी के दौरान किसी भी सोच में लोगों को सामाजिक रूप से स्वामित्व वाले संसाधनों की मदद से उत्पन्न मूल्य में एक उचित हिस्सा होना चाहिए।

तेलंगाना में भाकपा की पदयात्राएं

भाजपा हटाओ देश बचाओ

भाकपा राष्ट्रीय समिति के ''भाजपा हटाओ–देश बचाओ'' कार्यक्रम के आह्वान पर हैदराबाद में भाकपा नेताओं ने 21 अप्रैल 2023 (शुक्रवार) को पदयात्रा निकाली। पदयात्रा से पूर्व टैंक बंड पर डॉ. बी.आर. अंबेडकर की मूर्ति पर नेताओं ने फूल चढ़ाए उसके बाद पदयात्रा वहां से चलकर धरना चौक (इंदिरा पार्क) पहुंची। पदयात्रा के धरना चौक पर पहुंचने के बाद एक विशाल जन सभा हुई।

भाकपा राष्ट्रीय सचिवमंडल सदस्य डॉ. के. नारायणा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा सरकार की जन विरोधी और कॉरपोरेट परस्त नीतियों के बारे में जनता को बताना होगा और उनकी राजनीतिक चेतना बढ़ानी होगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई जनता का खून चूस रहा है तो यह मोदी सरकार है। हमें ग्रामीण लोगों द्वारा भोगी जा रही समस्याओं को चिन्हित करना होगा। नारायणा ने अम्बेडकर के उस कथन को उद्धृत किया जिसमें उन्होंने कहा था कि ''मैं तुम्हें पैसा नहीं दे रहा हूं लेकिन मैं तुम्हें वोट देने का अधिकार दे रहा हूं। यदि तुम इसका समुचित इस्तेमाल करोगे तो तुम कहीं भी अपना सिर ऊंचा कर चल सकते हो। लेकिन यदि तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो तुम्हें अपना सिर झुका कर चलना पड़ेगा''। नारायणा ने कहा कि गरीबों को अपने वोट का समुचित उपयोग करते हुए देश के शोषकों को हटाना होगा। यदि कम्युनिस्ट नहीं होते तो जमीन गरीबों के हाथ में न होती और जमींदारों का उस पर कब्जा होता। इनाम जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती और उस पर निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन इनाम जमीन पर मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और रियल स्टेट के बड़े खिलाड़ी इन जमीनों पर व्यापार कर रहे हैं। पुलिस इनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखेगी। लेकिन यदि बेघर लोग इस जमीन पर अपनी झोपड़ी खड़ी करेंगे तो पुलिस इस पर तत्काल कार्यवाही करेगी और उन पर हमला करेगी। सरकार भी पुलिस और भू–माफियाओं की मदद करती है। इस देश में जमीन की दिक्कत का आराम से समाधान हो सकता है। यदि लोग आंदोलन तेज करते हुए एक पैर जमीन पर और दूसरा पैर जेल में रखने को तैयार हों। मोदी जी के गोद लिए हुए 30 बेटे हैं। उनमें से 29 विदेश भाग गए हैं और एक देश में है उसका नाम अडानी है। मोदी सरकार देश की संपत्ति अडानी को सौंप रही है। यदि कॉरपोरेटों को दी जाने वाली छूट का दस प्रतिशत भी बेघरों पर खर्च किया जाए तो प्रत्येक बेघर का घर होगा। नारायणा ने मनरेगा बजट कम करने पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या देश में गरीबी कम हो गई है। कॉरपोरेट कंपनियों पर 33 प्रतिशत टैक्स को घटाकर 24–25

राम नरसिम्हा राव

प्रतिशत कर दिया है, पर आम आदमी भी समझ सकता है कि भाजपा किसका हित पूरा कर रही है। मोदी सभी तरीकों से हमारे देश को नष्ट कर रहे हैं। भाकपा देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और भाकपा ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी और भाकपा की देश के हर कोने में इकाईयां हैं तब चुनाव आयोग कैसे पार्टी की राष्ट्रीय मानयता को खत्म कर सकता है? नारायणा ने जोर देकर कहा कि हम इस मुद्दे को जनता की अदालत में लड़ेंगे।

भाकपा राष्ट्रीय सचिव सैयद अजीज पाशा ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सरकार बड़े बुर्जुआ और अडानी जैसी कॉरपोरेट कंपनियों के हितों के लिए काम कर रही है। मोदी के सत्ता में आने का नतीजा यह रहा कि जो भी वादे चुनाव के समय किए गए थे वे सभी कूड़ेदान में फेंक दिए गए। वो पूरी तरह महिलाओं, गरीबों और बेरोजगारों को नकार रहे हैं। अजीज पाशा ने जोर देते हुए कहा कि हम इस देश की जनता को सरकार की जन विरोधी और कॉरपोरेट परस्त नीतियों के बारे में बताएंगे।

भाकपा तेलंगाना राज्य सचिव कुनामनेनी संबाशिव राव ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि चुनाव आयोग या अन्य कोई संगठन लोगों के दिल में से कम्युनिस्टों को नहीं निकाल सकता। कई चुनाव आए और चले गए लेकिन चुनाव लोगों के दिलों से भाकपा को नहीं हटा सके। इस तरह के आयोगों द्वारा डाली गई जंजीर को कम्युनिस्ट तोड़ देंगे। यहां तक कि ब्रिटिश शासन में भाकपा पर प्रतिबंध लगाया हुआ था लेकिन भाकपा जनता के समर्थन से मुख्य धारा में आ गई। चुनाव आयोग मोदी के पिंजरे में कैद तोते की तरह बोल रहा है। कमयुनिस्ट जमीन के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन सरकार उनके खिलाफ मुकदमे कर रही है और हम लाठी, गोली, जेल आदि से नहीं डरते।

कम्युनिस्ट आंदोलन जगन्नाथ के रथ के जैसा है और सरकार एवं प्रशासन इस रथ के नीचे कुचले जाएंगे। लोगों की मांगों के लिए कम्युनिस्ट लाल झंडे तले जुझारू आंदोलन खड़े करेंगे।

चाडा वेंकट रेड्डी, भाकपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार गरीबों, दलितों और कमजोर तबकों के प्रति लापरवाही और भेदभाव कर रही है। सरकार को स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, घर और भोजन मुहैया कराना चाहिए। लेकिन अधिकांश लोग दवाई और शिक्षा की ऊंची कीमतों का खर्चा नहीं उठा सकते। चाडा ने दोहराते हुए कहा कि भाकपा अकेली पार्टी है जिसने देश की पूर्ण स्वाधीनता का नारा दिया था। भाकपा न्यायसंगत और कानूनी संघर्ष चला रही है। उन्होंने अम्बेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि वे कहते थे कि यदि शासक वर्ग ठीक से काम नहीं करता तो लोगों को अपनी मांगें संघर्षों से पूरी करवानी होगी।

इस महीने भर लंबी पदयात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों का पर्दाफाश किया जाएगा।

भाकपा (मा) राज्य सचिव सदस्य चेरुपल्ली सीतारामुलु ने अपने संबोधन में कहा कि भाकपा (मा) केंद्र और राज्य सरकार दोनों के खिलाफ लड़ेगी। मोदी के शासन में रोज–रोज जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। भाजपा और आरएसएस के लिए मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट प्रमुख शत्रु हैं। इसलिए वे कम्युनिस्टों को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। इसके बावजूद सीतारामुलु ने विश्वास दिलाया कि भाकपा (मा) कार्यकर्ता भी घर–घर जाकर प्रचार करने में हिस्सा लेंगे।

भाजपा हटाओ–देश बचाओ कार्यक्रम के तहत राज्य के सभी जिलों में पदयात्राएं आयोजित की गई। इन पदयात्राओं का राज्य सचिव सदस्यों, जिला सचिव सदस्यों एवं कार्यकारिणी सदस्यों ने नेतृत्व किया।

लेनिन की 153 वीं जन्म जयंती आंध्र प्रदेश में वाम दलों ने संयुक्त रूप से मनाई

लेनिन की 153 वीं जन्म जयंती के अवसर पर भाकपा, भाकपा (मा), भाकपा (माले) न्यू डेमोक्रेसी, अखिल भारतीय किसान सभा और आ.प्र. प्रजा नाट्यमंडली (इप्टा राज्य इकाई) साथियों ने संयुक्त रूप से विजयवाड़ा स्थित लेनिन सेंटर पर लेनिन को श्रद्धांजलि के रूप में पुष्पांजलि अर्पित की। मार्क्स–एंगेलस–लेनिन मेमोरियल कमेटी की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

लेनिन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद एक सभा की गई, सभा की अध्यक्षता मार्क्स–एंगल्स–लेनिन मेमोरियल कमेटी के संयोजक बुद्दिगा जमींदार ने की। भाकपा आंध्रप्रदेश राज्य समिति सचिव के रामाकृष्णा ने अपील करते हुए कहा कि, विश्व इतिहास में रूसी क्रांति के अग्रिणी नेता लेनिन का विशिष्ट स्थान है, हमें लेनिन से प्रेरणा लेते हुए साम्राज्यवादी शोषण के खिलाफ लड़ना होगा, हमें शोषण के सतत बदलते रूपों के बरक्स अपनी रणनीति तैयार करनी होगी। भारत में सांप्रदायिक और कॉर्पोरेट ताकतें बिना किसी आपसी टकराव के फल–फूल रही हैं और आम जनता उत्पीड़ित हो रही है एक की हिंसा सड़कों पर नजर आती है तो दूसरे की हिंसा कार्यस्थलों की चारदीवारी के अंदर श्रम कानूनों के उल्लंघन से होती है, दोनों ही हिंसाओं को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से राज्य–सरकार का समर्थन है। इस पृष्ठभूमि में कम्युनिस्ट के बतौर हमें एक जुट होकर इस शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ना होगा और क्रांतिकारी

राम नरसिम्हा

आंदोलन निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना होगा।

भाकपा (मा) आंध्र प्रदेश राज्य सचिव वी. श्रीनिवास राव ने अपने संबोधन में कहा कि लेनिन एक महान व्यक्ति थे उन्होंने अपने समय की राजनीति पर मार्क्सवादी समझ से रणनीति तैयार करते हुए एक मजबूत क्रांति का निर्माण किया। लेनिन ने जहाँ रूस में मजदूरों–किसानों का नेतृत्व किया वहीं साम्राज्यवादी देशों के अधीन देशों को साम्राज्यवादी चंगुल से निकलने के लिए लामबंद होने के प्रेरित किया।

आंध्र प्रदेश के जानेमाने साहित्यकार ने अपने संबोधन में कहा कि स्टालिन ने सैद्धांतिक रूप से लेनिनवाद को समझाया। रूसी क्रांति मजदूर वर्ग की क्रांति थी जो की साम्राज्यवाद के खिलाफ उभरी। भारत साम्राज्यवाद का एक बड़ा बाजार बन गया है। हमें साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ जुझारू लड़ाई खड़ी करनी होगी।

एमएलसी के. एस. लक्ष्मण राव ने अपने संबोधन में कहा कि लेनिन की कृतियां "राज्य और क्रांति", "साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है", "क्या करना है?" आदि आज भी मौजूदा परिस्थितियों को समझने, बदलने की दिशा में सोचने और काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। भाकपा (मा) राज्य नेता सुब्बारम्मा ने अपने संबोधन में रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक समानता का जिक्र किया। भाकपा (माले) न्यू डेमोक्रेसी के राज्य नेता एम रामकृष्णा ने कहा कि हमें इस शोषणकारी समाज से इंसानों की मुक्ति के लिए संघर्ष करना होगा। आंध्र प्रदेश प्रजा नाट्यमंडली के साथियों द्वारा क्रांतिकारी गीतों से सभा में जोश छाया रहा। भाकपा सिटी सहायक सचिव नक्का वीरभद्र राव ने सभा में उपस्थित सभी साथियों को धन्यवाद दिया ।

स्कूली किताबों से डार्विन को हटाना दकियानूसी सोच को बढ़ाना

डा. सोमा मार्ला

पिछले सप्ताह कई वैज्ञानिकों, शिक्षकों ने सीबीएसई के दसवीं कक्षा के विज्ञान पाठ्यक्रम से एनसीईआरटी द्वारा विकास के सिद्धांत को हटाने के बारे में गंभीर चिंता जताई थी।

वैज्ञानिकों ने एनसीईआरटी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को लिखे एक पत्र में कहा कि, विकास की प्रक्रिया को समझना वैज्ञानिक सोच के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस रहस्योद्घाटन से विद्यार्थियों को वंचित करना 'शिक्षा से छेड़छाड़' है। दुःख की बात है, हटाए गए विज्ञान विषयों की सूची में शामिल हैं, चार्ल्स डार्विन, आणविक फाइलोजेनी, विकास और विकासवादी संबंध को समझना।

वैज्ञानिकों ने पाठ्यक्रम से विकास के सिद्धांत को हटाने के खिलाफ अपील की और इसकी तत्काल बहाली की मांग की। हस्ताक्षरकर्ताओं में आईआईटी, आईआईएसईआर, आईसीएआर, टीआईएफआर, सीएसआईआर और अन्य केंद्रीय और विश्वविद्यालयों के प्रमुख वैज्ञानिक शामिल हैं। विकासवादी जीव विज्ञान के बारे में ज्ञान और समझ न केवल जीव विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उसके आसपास की प्रकृति में मनुष्य के जीवन और स्थान की संरचना को समझने की कुंजी है। विकासवादी जीव विज्ञान मानव रोगों से लेकर महामारी विज्ञान, पारिस्थितिकी, पर्यावरण से लेकर दवा खोज तक समाज में दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं के विश्लेषण में मदद करेगा।

हालांकि हम अपने व्यस्त दैनिक जीवन में महसूस नहीं करते हैं, लेकिन प्राकृतिक चयन ने हाल ही में कोविड वायरल रोगाणु (पेथोजेन) के जीनोम का विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, कोविड वायरल रोगाणु के जीनोम विश्लेषण से इसके कई उप वर्गो की लड़ों में क्रमिक विकास और परिवर्तन का पता चलता है। इन वैज्ञानिक जांचों ने महामारी को फैलने से रोकने में महामारी विज्ञान की मदद की है। वायरल जीनोम विकास अध्ययन ने रोगाणु (पेठोजेन) में जीन और एंजाइम पैदा करने वाले विभिन्न रोगों को समझने में बहुत मदद की, जिससे अंततः विभिन्न टीकों की खोज हुई जिसने लाखों मानव जीवन को बचाया।

हमारा ग्रह (विभिन्न प्रजातियों के) जानवरों, पौधों, सूक्ष्मजीवों की विविधता से भरा हुआ है। विभिन्न प्रजातियों के बीच जैव विविधता और मौजूदा संबंधों को समझने से वैज्ञानिकों को संबंधित पौधों को हाइब्रिड करने और बेहतर फसलों को अपनाने के साथ इसने खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में और हमारे ग्रह को भूख से बचाने में मदद की। डार्विन के उत्पत्ति के सिद्धांत ने हमें यह समझने में मदद की कि कैसे विभिन्न पौधे और जानवर पर्यावरण में खतरों के सामने आने पर बेहतर उत्तरजीविता के लिए धीरे–धीरे अन्य प्रजातियों में बदल जाते हैं।

जीव विज्ञान ने हमें सिखाया कि सभी जीव डीएनए या आरएनए, चयापचय (मैटाबोलिज्म), शरीर क्रियाविज्ञान, साझा आनुवंशिक कोड (जीवन योजना) के विरासत की एक साझा संरचना साझा करते हैं। आनुवंशिकी (जेनेटिक्स) जीवविज्ञान का एक क्षेत्र है, जो डार्विन के विकास के युग प्रवर्तक सिद्धांत के बाद फल–फूल रहा है और इसने जीवन वृक्ष का उपयोग करते हुए विभिन्न जानवरों के बीच समानताओं और पारस्परिक संबंधों को आकर्षित करने में मदद की है। फ्रेडरिक एंगल्स ने एक निबंध में वनमानुष से मनुष्य में परिवर्तन में श्रम की भूमिका के माध्यम से मानव के विकास की वर्तमान सभ्यता चरण का विश्लेषण किया और विकास की प्रक्रिया में मानव श्रम द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की।

विकास की सार्वभौमिक समझ के विपरीत, (जनवरी, 2018 में) भाजपा नेता मा. सत्यपाल सिंह जो कि उस समय मानव विकास संसाधन विकास मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने न केवल डार्विन के विकास के सिद्धांत को चुनौती दी, बल्कि कहा कि "किसी ने भी वानरों को मनुष्य में बदलते नहीं देखा"। उन्होंने आगे कहा कि "डार्विन का मानव का विकास का सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से गलत है। इसे स्कूल और कॉलेज पाठ्यक्रम में इसे बदलना होगा"।

इसलिए, आज डार्विन के विकासवादी सिद्धांत, यूक्लेडियन ज्यामिति को हटाना और उन्हें काल्पनिक दशावतारों और वैदिक गणित के साथ बदलना और इस पृष्ठभूमि में रचनात्मकता के सिद्धांत का समर्थन कोई आश्चर्य नहीं है। आरएसएस और वर्तमान शासन विज्ञान, तर्कसंगत सोच को लक्षित कर रहे हैं ताकि छात्र के दिमाग से 'आलोचनात्मक विचार' और 'सवाल' को खत्म किया जा सके। यह आधुनिक भारत को अज्ञानता, मनुस्मृति और जातिवाद के अंधकारमय युग तक ले जाने के एक बड़ी चाल का हिस्सा है।

इसलिए आईआईटी, आईआईएसईआर, आईसीएआर, टीआईएफआर, सीएसआईआर और अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लगभग 1800 प्रमुख वैज्ञानिकों, शिक्षकों ने पाठ्यक्रम से विकास को हटाने के विरोध में अपील की और इसे तत्काल पाठ्यक्रम में जोड़ने की मांग की है। हस्ताक्षरकर्ताओं में प्रमुख वैज्ञानिक शामिल हैं। जनगण को स्कूली पाठ्यक्रम से हटाई गई विषयवस्तु को फिर से पाठ्यक्रम में तत्काल जोड़ने के लिए एनसीईआरटी और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मांग करने में वैज्ञानिकों के साथ शामिल होना चाहिए।

'पश्चिमी ज्ञान' को 'भारतीय ज्ञान' से बदलने से बौद्धिक अनर्थ हो सकता है

जी एन देवी

यह एक जटिल कहानी है कि ज्ञान परंपराओं के विकास को अब पूरे विश्व में 'पश्चिमी ज्ञान' के रूप में अद्वितीय माना जाता है। ज्ञान परंपराओं के विकास ने प्राचीन समय में कई सभ्यताओं और आधुनिक समय में कई महाद्वीपों से प्राप्त कई ज्ञान की उप–धाराओं को शामिल किया है, लेकिन ये समस्त ज्ञान आधुनिक यूरोप में विकसित ज्ञान के एक तर्क–आधारित मैट्रिक्स (साँचे) के रूप में एक साथ बुना हुआ है। जटिलता इतनी अधिक है कि उस ज्ञान प्रणाली के सभी मूलों का पता लगाना असंभव होगा। फिर भी, पूरी प्रक्रिया के केंद्र में प्रमाण योग्य अमूर्त के अंग की बौद्धिक परिणाम के रूप में ज्ञान की एक अवधारणा थी।

पश्चिमी प्रणाली ज्ञान को ' लोगोज' (शब्द/चित्र/चिन्ह) के रूप में देखती है। इसके विपरीत भारतीय विचारों की परंपराओं आस्तिक और नास्तिक दोनों ही में ज्ञान को एक अनुभव के रूप में देखा गया, भारतीय विचार परम्पराओ में ज्ञान को "जानने" (एक क्रिया) के रूप में, एक आंतरिक उपलब्धि के रूप में, या ग्रीक शब्द "नोसिस" (आध्यात्मज्ञान) के रूप में देखा गया।

संस्कृत के दो शब्द विद्या और ज्ञान, दोनों परंपराओं के बीच बुनियादी अंतर का सही प्रतिनिधित्व करते हैं। भाषाओं में, एक क्रिया–आधारित संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन सांस्कृतिक इतिहास में यह प्रक्रिया लगभग असंभव है। एक परंपरा "विचार" या तार्किकता को विशेष महत्व देती है औ दूसरी विचार परंपरा "अन्तर्ज्ञान'' या अनुभव की आंतरिक क्षमता को प्राथमिकता देती है।

एक परंपरा बोध को तार्किक कथन या सिद्धांत के रूप में लाने की पद्यतियों को विकसित करने का प्रयास करती है, दूसरा ज्ञान परंपरा बुद्धिमत्ता के उस पूर्व–अस्तित्वमान महासागर और चेतना जो उस तक पहुँचने की आकांक्षा रखती है के बीच जैविक संबंध को घनीभूत करती है । सरल शब्दों में, दोनों ज्ञान परम्पराएं भौतिक रूप में, सांस्कृतिक धरोहरों के रूप में वैसे ही अलग हैं जैसे की हमारे आसपास की वास्तविकता का वर्णन अलग है। दोनों ज्ञान परम्पराएं एक दूसरे को काट सकती है, लेकिन अगली पीढ़ी को शिक्षित करने की कोई भी अमिश्रित व्यवस्था कदाचित ही साथ–साथ उपयुक्त हो सकती है।

सीखने की भारतीय परंपराओं में, पुराने समय से ही स्मृति "स्मरण" साथ ही साथ "विशिष्ट स्मृति" एक प्रमुख रुचि थी। भगवद् गीता में बल्कि एक स्पष्ट कथन है कि स्मृति के कमजोर होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है – स्मृति–भ्रष्ट बुद्धि–नाश। प्राचीन सैद्धांतिक रचनाओं में, विभिन्न सुगम स्मृति सहायक साधनों के माध्यम से किसी पाठ को याद रखने लायक बनाए रखने के लिए खास ध्यान दिया जाता था, यह वैसे ही जैसे कि ग्रीक परंपरा में सिसेरो द्वारा ग्रीक स्मृति सहायक तरीके का इस्तेमाल किया गया था।

प्राचीन भारतीय साहित्य का बड़ा हिस्सा, विविध दार्शनिक स्कूलों के विचार, को सटीकता के बहुत उच्च मानक के साथ याद करके संरक्षित किया गया। सीखने के प्रमुख साधन के रूप में स्मृति के विकास पर आसक्त दक्षिण एशियाई सभ्यता के अलावा ऐसी कोई अन्य सभ्यता नहीं है।

यूरोप में 17वीं शताब्दी में स्मृति के इस्तेमाल में जो भिन्नता आई इसके कारण इसे यूरोप में 'सार्वभौमिक ज्ञान' कहा गया था, और भारत में विचारों के इतिहास में स्मृति का जो प्रयोग था उसे उनसे समर्थन नहीं मिला जो 'ज्ञान के विज्ञान' के विचार या 'सार्वभौमिक ज्ञान' को ज्ञान समझते थे।

अतीत के पाठों के त्रुटिरहित पुनरुत्पादन के लिए स्मृति के परिष्कृत प्रयोग के साथ, जानने के रूप में ज्ञान का विचार, बुद्धि को अंतर्ज्ञान करीब ले आया जो की 'प्रशिक्षुता' (अप्रेन्टिसशिप) में बदल गया था जैसा कि पहले बताया गया यह ज्ञान न केवल चिकित्सा, रसायन विज्ञान, मूर्तिकला, वास्तुकला, धातु विज्ञान, नृत्य, संगीत और शिल्प की शिक्षा लेने या देने का पंसदीदा तरीका बन गया था बल्कि दर्शन, खगोल विज्ञान और खगोल विज्ञान जैसे विषयों में भी, जिनमें अमूर्तता और नए रूप में प्रश्न उठाने की क्षमता है।

2,000 वर्ष पहले भारतीय समाज के भीतर स्थापित सामाजिक अलगाव के साथ, ज्ञान को विकसित करने की प्रशिक्षुता (इंटर्नशिप) पद्धति किसी भी वास्तविक रूप से 'सार्वभौमिक विज्ञान' के निर्माण में एक बड़ी बाधा बन गई। विचारों में विकास के भंडारण के लिए एक उपकरण के रूप में भंडारण के लिए अत्यधिक सटीक समरण रखने वाली पद्धति जारी रही लेकिन इस स्मरक ज्ञान को कौन व्यक्ति हासिल कर सकेगा यह उसके सामाजिक स्तर से सीमित था।

परिणाम यह था कि औपनिवेशिक काल में स्मृति–आधारित ज्ञान विस्तृत–श्रेणी की दो व्यापक धाराओं का सह–अस्तित्व बिना किसी पारस्परिक आदान–प्रदान और मिश्रित–संवर्धन की संभावना के बिना जारी रहा–एक, स्मृति परंपराओं की विस्तृत–श्रेणी, उन लोगों की थी जिनके पास लेखन सहित अमूर्त प्रतीकों तक पहुंच थी, और दूसरी स्मृति परंपराओं की विस्तार श्रेणी उन लोगों की थी जिन्हें प्रतीकात्मक अमूर्तता के प्रयासों से से रोका गया था।

भारत में 13 वीं शताब्दी के दौरान कागज के उपयोग के लिए उपलब्ध होने के साथ इस तरह की स्कूली शिक्षा बदल गई थी। हालांकि, मौखिक का स्थान पूरी तरह से या पर्याप्त रूप से लिखित द्वारा नहीं लिया गया था। दोनों ने ज्ञान के भारतीय उत्पादन में अंतरसंबंधित तरीके से सहयोग किया। जब कागज उपलब्ध हुआ, तो विद्वानों ने लेखन के लिए कागज का उपयोग किया। पहले वे पेड़ की छाल का इस्तेमाल करते थे। कई पीढ़ियों से छात्र पांडुलिपियों की सावधानीपूर्वक प्रतिलिपियां तैयार करते थे और हर कुछ सौ वर्षों में उनकी फिर से प्रतिलिपियाँ तैयार की जाती थी । लेकिन कुछ दूसरे लोग भी थे जिन्होंने इसे याद किया और परवर्ती पीढ़ी को बोली के के माध्यम से ज्ञान को जारी रखा। इसलिए पांडुलिपि एक ही समय में

शेष पेज 14 पर...

भाजपा हटाओ देश बचाओ

मणिपुर में भाकपा का राष्ट्रीय अभियान

एम. जोयकुमार लुवांग

15 अप्रैल, 2023 को मणिपुर भाकपा ने केंद्र और मणिपुर राज्य में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए राष्ट्रीय राजनीतिक अभियान शुरू किया। राज्य परिषद ने महीने भर चलने वाले अभियान का उद्घाटन किया जो भाकपा की राष्ट्रीय परिषद का आह्वान था। आरएसएस/बीजेपी के खतरनाक शासन के सवालों पर भाकपा राज्य परिषद के नेताओं के भाषणों से जन संगठनों के नेता, कार्यकर्ता और मीड़िया के लोग सहमत दिखे। विरोध सभा राष्ट्रव्यापी राजनीतिक अभियान की आयोजन समिति द्वारा आयोजित की गई थी। डॉ. एम. नारा, राष्ट्रीय कंट्रोल कमीशन सदस्य, भाकपा राज्य सचिव एल. थोरेन, पूर्व भाकपा राज्य सचिव एल सोतिनकुमार, भाकपा राज्य सहायक (संगठन) सचिव एम जॉयकुमार, सहायक सचिव और आयोजन समिति के संयोजक (राजनीतिक) एन सिंहजीत और एस सोरोजिनी देवी पूर्व अध्यक्ष, सभी मणिपुर नूपी मारुप प्रेसिडियम के सदस्य थे। एन. सिंहजीत ने इस अभियान महत्व को बताते हुए मेहनतकश लोगों के नागरिक और लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने वाली सरकार की जनवाद विरोधी गतिविधियों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को खतरा बन रही है। एम. जॉयकुमार ने कहा कि आरएसएस की खतरनाक विचारधारा ही है, जो समानता, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और समाजवाद को खत्म कर रही है। यहां तक कि वे स्वतंत्र भारत के संवैधानिक प्रावधानों और विचारों को नष्ट कर अधिकारों को चुनौती दे रहे हैं।

राज्य सचिव एल. थोरेन ने अल्पसंख्यकों की स्थिति की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों का शोषण हो रहा है और जातिगत अत्याचार बढ़ रहे हैं और मनुवादी आदेश के तहत सामाजिक समरसता और लोगों की प्रगति आरएसएस–भाजपा शासन में छिन्न भिन्न हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि क्रोनी कैपिटलिज्म जो हमारे देश के कीमती संसाधनों को ख रहा है उसे सरकार द्वारा उकसाया जा रहा है। अडाने समूह के कदाचारों पर द हिंदू

बीइंग रिसर्च की रिपोर्ट ने मोदी सरकार की मिलीभगत को जाहिर कर दिया है।

उन्होंने कहा कि पार्टी सदस्य, हमदर्द, मणिपुर के आम लोग, हमारे अभियान का हिस्सा बने सभाओं में आयें और विरोध में सडकों पर उतरें और धरने पर बैठें।

एल सोतिनकुमार ने शीर्ष स्तर पर हो रहे बड़े पैमाने पर और संस्थागत भ्रष्टाचार के बारे में भी विचार व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि निजीकरण फैल रहा है और राष्ट्रीय संपत्ति चंद लोगों को बेची जा रही है, जबकि बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा कमा रही है और एलआईसी और एसबीआई जैसे समय–जाने माने संस्थानों को भी मोदी के क्रोनियों से खतरा हो रहा है। लोगों की गाढ़ी कमाई का इस्तेमाल भाजपा द्वारा सार्वजनिक वस्तुओं के वित्तपोषण के बजाय कुछ पूंजीपतियों को वित्तपोषित करने के लिए किया जा रहा है।

एस सोरोजिनी ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बारे में बात और कहा कि यह अभूतपूर्व क्रूरता के साथ बढ़ी है और भाजपा नेता सांसद और राज्य विधानसभाओं में बैठे नेता कई महिला हिंसा के अपराधों में अपराधी है। और उन्होंने बच्चों के अधिकारों के बारे में भी बात की।

डॉ. एम. नारा सिंह ने अक्टूबर 2022 में विजयवाडा में आयोजित भाकपा की 24वीं पार्टी कांग्रेस के महत्व का जिक्र किया, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक शिक्षा, भूमि, आवास और खाद्य सुरक्षा को हमारे एजेंडे की मूलभूत मांगों के रूप में इंगित किया गया था।

उन्होंने भारत में किसानों की समस्याओं को भी इंगित किया कि किसान आंदोलन में 700 से अधिक शहीदों के बाद ही सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा फिर भी किसानों की मांगें पूरी नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा कि ये हैं हमारी मांगें:

–भाजपा सरकार को उखाड़ फेंको। देश को बचाने के लिए और देश के लोगों को बचाने के लिए,

–सार्वजनिक संपत्तियों का निजीकरण बंद करो,

–भ्रष्टाचार बंद करो,

–मनरेगा फंड कम नहीं होना चाहिए,

–कृषक समुदाय को बचाओ, कृषि को बचाओ और जंगल और पर्यावरण को बचाओ

–मणिपुर की सीमा को म्यांमार द्वारा घुसपैठ की स्थिति से सुरक्षित करो,

–भारत का संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, धर्मनिरपेक्षता बचाओ, समाजवाद बचाओ।

16 अप्रैल 2023 को राज्य परिषद ने इन निम्नलिखित इलाकों में हमारी संबंधित स्थानीय परिषदों द्वारा 6 बैठकों और रैलियों का आयोजन किया इरावत पार्क में कांगमोंग लामलाई स्थानीय में, कोन्थौजम स्थानीय चरंगपत गांव में, चेलौयू वांगखोम स्थानीय निंगथेम पुखारी की तरफ, येसकुल स्थानीय, इंफाल में सिंगामेई लोकल वबगई बाजार में, वाबगई लोकल कई पार्टी शाखाओं में आयोजित सभी सभाओं में हजारों पोस्टर और हैण्डबिल बांटे गये और 21 तारीख को हमने खांगाबोक स्थानीय के तहत थौबल जिले के खागाबोक बाजार में एक रैली का आयोजन किया।

यह अभियान और रैलियां 15 मई तक जारी रहेंगी। इनका समापन एक विशाल जनसभा में होगा।

मनरेगा की समस्याओं पर खेत मजदूर यूनियन के धरने

तिरुचिरापल्ली जिला वैयमपट्टी पंचायत यूनियन मुगवानुर पंचायत में मनरेगा योजना में ऑनलाइन उपस्थिति पंजीकरण में त्रुटि को दूर करने के लिए मुगवानुर पंचायत दफ्तर के सामने 17 अप्रैल 2023 को भारतीय खेत मजदूर यूनियन की ओर से धरना दिया गया। धरने की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष ए डी शनमुकानंदम ने की। जिला सचिव पी गणेशन ने धरना शुरू किया।

धरने के बीच शाम को शांति वार्ता हुई। पिछले मार्च माह में काम करने वालों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में तीन दिन, चार दिन, पांच दिन छूट दी गई हैं। गैर–पंजीकृत कार्य दिवसों के लिए मजदूरी का भुगतान न किए जाने को इंगित किया गया था। अधिकारी ऑनलाइन पंजीकरण में लापता लोगों को तुरंत मजदूरी का भुगतान करने पर सहमत हुए।

वे तुरंत आधार को लिंक करने और उन लोगों को नौकरी देने पर सहमत हुए जिन्हें इस आधार पर काम पर आने से रोका गया था कि आधार को मनरेगा जाबकार्ड से लिंक नहीं किया गया था।

वे किये हुए काम का तुरंत वेतन देने पर सहमत हुए, जिनका वेतन बकाया था।

उनकी मांगों को स्वीकार करने की आधार पर धरने को समाप्त कर दिया गया। इस संघर्ष में सर्कल नेता एम

रामासामी, थंगरासु, स्टीफनसेकर, बालन और आरोक्यम सहित अस्सी लोगों ने भाग लिया।

तिरूमपुरी

तरुमपुरी जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने खेत मजदूरों ने प्रदर्शन किया। उनकी मांगें थी:

–भूमिहीन खेत मजदूरों को आवास के लिए जमीन।

–400 वर्ग फीट स्थल पर पक्का मकान बनाने केलिए छह लाख रुपए अनुदान दिया जाए।

–छोटे और सीमांत किसानों सहित खेत मजदूरों को 3000 रुपये मासिक पेंशन देने के लिए अलग पेंशन कानून पारित किया जाना चाहिए।

–पेयजल, मुफ्त शिक्षा, चिकित्सा सुविधा

इन मांगों को लेकर तरुमपुरी जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने 24 अप्रैल 2023 को भारतीय खेत मजदूर यूनियन की ओर से प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष जि. माथैयन ने की। जिला सचिव जे प्रदाबन ने मांगों को समझाया और उनका समाधान किया। इसमें जिला उप सचिव जी. पच्चकाउंटर, जिला उपाध्यक्ष जी. राजगोपाल, एन मुरुगेसन और कार्यकारणी और जिला समिति सहित बडी संख्या में खेत मजदूर शामिल हुए। जिला कलेक्टर को नौ सूत्रीय मांग ज्ञापन दिया गया था।

भाजपा हटाओ देश बचाओ

भाकपा के जन अभियान को मिल रहा है व्यापक जन समर्थन

भाकपा राष्ट्रीय परिषद के आह्वान पर देशभर में जारी भाजपा हटाओ, देश बचाओ को व्यापक जन समर्थन हासिल हो रहा है। देश के सभी राज्यों में भाकपा भाजपा हटाओ, देश बचाओ के नारे के तहत जन अभियान चला रही है। जिसे पूरे राज्य में जन समर्थन मिल रहा है।

राजस्थान

जयपुर: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य कार्यकारिणी ने पूरे राज्य में पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान भाजपा हटाओ–देश बचाओ संविधान बचाओं के क्रियान्वयन के लिये जिला इकाईयों को व्यापक तैयारियों के साथ सफल बनाने का आह्वान किया गया। पार्टी की समस्त जिला ईकाइयाँ 14 अप्रैल को जिला मुख्यालयों पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर संविधान लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लेते हुए राष्ट्रीय आह्वान को सफल बनाने के कार्यक्रम आयोजित किये गये। शाहपुरा (भीलवाड़ा): भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला भीलवाड़ा द्वारा 14 अप्रैल को शाहपुरा में पार्टी के पूर्व राज्य सचिव वामपंथी चिंतक कामरेड दुष्यंत ओझा की तृतीय पुण्य तिथि पर 'विचार गोष्ठी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समक्ष चुनौतियाँ' आयोजित की गई जिसमें पार्टी के अन्य जिला इकाईयों उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के साथी उपस्थित रहे। इस विचार गोष्ठी के पश्चात् शाहपुरा बी. आर. अम्बेडकर पार्क में एकत्रित होकर उन्हें माल्यार्पण किया गया और संविधान लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लिया।

पार्टी के राज्य सचिव नरेन्द्र आचार्य ने कहा, भाजपा नीत मोदी सरकार संविधान, लोकतंत्र संविधानिक संस्थाओं पर हमले कर रही है। हमारी सांझी संस्कृति सांझी विरासत को तोड़ा जा रहा है, साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जा रहा है। पार्टी ने अपनी विरासत बचाने लोकतंत्र संविधान की रक्षा करने के इस 14 अप्रैल से 15 मई तक पदयात्रा कार्यक्रम सभी जिलों ध तहसील ध शाखा स्तर पर आयोजित करने का आह्वान किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता तारासिंह सिद्धू ने कार्यकर्ताओं को पार्टी के इस राष्ट्रीय आह्वान को सफल बनाने के लिए तहसील स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाकर तमाम जनसंगठनों को शामिल कर इस अभियान को गाँव–गाँव, ढाणी–ढाणी लेकर जावें। तारासिंह सिद्धू, नरेन्द्र आचार्य ने उदयपुर के जिला सचिव सुभाष श्रीमाली, हिम्मत चांगवाल, कालू, मोहन खराड़ी तथा चित्तौड़गढ़ के साथी राधा भण्डारी, गीता छीपा, प्रभात कुमार व भीलवाड़ा जिला सचिव कैलाश गहलोत को पार्टी के झण्डे देकर अपने–अपने जिलों में पदयात्रा कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया।

जयपुर: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जयपुर जिला द्वारा 14 अप्रैल को पार्टी कार्यालय में युवाओं की वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के साथी प्रेमजी ने युवाओं को पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान को सफल बनाने के लिये आने वाले दिनों में और तैयारी के साथ जनता के बीच जाकर संविधान लोकतंत्र पर हो रहे हमले, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, श्रम कानूनों के खिलाफ लामबंद करेंगे। इस कार्यक्रम में निशा सिद्धू ने भी पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया। प्रेमजी, आमीन अली, राजेश, नईमुद्दीन, ईशा शर्मा ने वाहन रैली का नेतृत्व किया।

बीकानेर: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल, 2023 को सुबह 11.00 बजे भाकपा के जिला सचिव अविनाश चन्द्र व्यास एवं जिला सहायक सचिव सरजू गहलोत के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय मदन अजमानी भवन, अलख सागर से अम्बेडकर सर्किल तक पैदल मार्च किया। पार्टी की ओर से वयोवृद्ध साथी प्रसन्न कुमार शर्मा ने बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर डॉ. अविनाश चन्द्र व्यास ने कहा कि डा. बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने निजी हितों की दरकिनार करते हुए संविधान में दलित, वंचित, शोषित लोगों की आवाज को ताकत दी, परन्तु वर्तमान समय में केन्द्र की मोदी सरकार के द्वारा संविधान विरोधी कार्य कर संविधान को कमजोर किया जा रहा है। बाबा साहेब के सपनों का भारत तभी बन सकता है, जब समाज के हर वर्ग की सत्ता में हिस्सेदारी हो। व्यास ने कहा कि देश की जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है और केन्द्र की मोदी सरकार साम्प्रदायिक जैसे मुद्दों को लाकर देश की जनता और नौजवानों को गुमराह कर रही है। ऐसे में समय आ गया है कि देश जनता धर्म, जाति और साम्प्रदायिक राजनीति से ऊपर उठकर केन्द्र की मोदी सरकार को 2024 के आम चुनावों में शिकस्त देवें। प्रदर्शन में पार्टी और उनके जनसंगठनों से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर पार्टी के जिला सहायक सचिव डॉ. सरजू गहलोत, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) बीकानेर अध्यक्ष प्रस्न कुमार शर्मा, महामंत्री अब्दुल रहमान कोहरी, रोडवेज के तेजपाल लखारा, हंसेरा किसान सभा के हुकमाराम मेघवाल, लॉयर एसोसिएशन की ओर से महेश कुमार जोशी सहित अनेक लोगों ने शिरकत की।

रानीवाड़ा: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला जालौर की भाजपा हटाओ देश बचाओ अभियान के तहत रैली का आयोजन रानीवाड़ा मुख्यालय पर किया गया। पार्टी के जिला सचिव ईशाराम बिश्नोई ने बताया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के निर्णय अनुसार ''भाजपा हटाओ–देश बचाओ–संविधान बचाओ–देश बचाओ" के नारों के साथ बाबा साहब की मूर्ति को माल्यार्पण कर रानीवाड़ा के मुख्य बाजारों से नारेबाजी करते हुए सांचौर रेलवे क्रॉसिंग पर समाप्त हुई। रैली में संविधान बचाओ–देश बचाओ–भाजपा हटाओ देश बचाओ, मंदिर मस्जिद की राजनीति बंद करो'' नारे लगाते हुए हाथों में तख्तियाँ और झंडे लिए चेतना रैली निकाली गई। मकाराम चौधरी ने कहा कि वर्तमान केन्द्र सरकार द्वारा संविधान के साथ छेड़छाड़ करना, सांप्रदायिक सद्भावना को तोड़ना तथा धार्मिक उन्माद फैलाकर नफरत की राजनीति करना देश हित में नहीं है। विरद सिंह चौहान ने कहा कि केन्द्र केन्द्र सरकार द्वारा पूंजीपतियों को बढ़ावा देकर निजीकरण किया जा रहा है और मंदिर मस्जिद के नाम पर जनता का ध्यान मूल समस्याओं से हटाया जा रहा है। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को कौड़ियों के भाव पूंजीपतियों को बेचकर देश के साथ धोखा किया जा रहा है। चेतना रैली 14 अप्रैल, 2023 से 15 मई, 2023 तक पूरे देश में आयोजित की जाएगी। रैली के समापन स्थल पर रानीवाड़ा उप प्रधान महादेवा राम देवासी ने रैली का स्वागत किया और धन्यवाद ज्ञापित किया। रैली में जोगाराम सुथार, भारमल सेंडिया, रिड़मल सिंह गुंदाऊ, आसूराम गोदारा, जोराराम रूपावटी, नेनाराम प्रभु राम कोजाराम, धनराज मेघवाल, परबताराम सहित सैकड़ों लोग शामिल रहे।

अलवर: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला अलवर द्वारा पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान की शुरुआत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया, जिसका विषय "संविधान में प्रदत्त अधिकारों और उनकी अनुपालना'' था। गोष्ठी में वक्ताओं ने भारतीय संविधान में जनता को मिले अधिकारों और उसे आमजन तक पहुँचाने पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार अपनी जनविरोधी नीतियों के माध्यम से संविधान व लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, जिससे समाज में असमानता बढ़ रही है। देश में बेरोजगारी महँगाई से जनता का ध्यान हटाने के लिये धर्म, जाति, सम्प्रदाय के नाम जनता को गुमराह किया जा रहा है। संविधानिक संस्थाओं पर हमसे हो रहे है देश में भय, नफरत का वातावरण बनाया जा रहा है। पार्टी अपने राष्ट्रीय आह्वान के साथ जनता के बीच जाकर उनके मुद्दों को पुरजोर से उठाकर संघर्ष करेगी। गोष्ठी में पार्टी जिला सचिव जगदीश शर्मा, राजकुमार बख्शी, भोलाराम, तेजपाल सैनी, सीपीएम जिला सचिव – रईशा, रघुनाथ वबेजा (सीटू), हरिशंकर गोयल, वीरेन्द्र चौधरी (आरसीटू)।

पटना (बिहार)

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉ. भीम राव अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल से शुरू की गई भाजपा हटाओ, देश बचाओ पदयात्रा को गांवों में व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। पदयात्रा 15 मई तक चलेगी। भाकपा के राज्य सचिव राम नरेश पाण्डेय ने बयान जारी कर कहा कि राज्य के सभी 38 जिलों में पार्टी के कार्यकर्ता गांव–गांव पदयात्रा के माध्यम से केन्द्र सरकार की जनविरोधी नीतियों को उजागर कर रहे हैं। जन समस्याओं को एकत्रित किया जा रहा है। जन सवालों को लेकर आठ और नौ जून को बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर जन सत्याग्रह और जेल भरो आन्दोलन किया जाएगा। पदयात्रा के दौरान सत्याग्रहियों की सूची भी तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि जनता अपनी समस्याओं को पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के समक्ष रख रहे हैं। मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों से जनता तबाह है। महंगाई आसमान छू रही है। डीजल, पेट्रोल और घरेलू गैस की मूल्य वृद्धि से लोग परेशान हैं। किसानों को समय पर खाद बीज नहीं मिल पाता है। मिलता भी है तो ऊँची कीमतों पर मिलता है। किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य तो दूर की बात है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी किसानों की उपज खरीदी नहीं जा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा मनरेगा के बजट में की गई कटौती का असर गांवों में रोजगार पर दिखने लगा है। गरीबों और मजदूरों के समक्ष रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को कार्य नहीं मिल रहा है। मनरेगा की मजदूरी बहुत ही कम है। लोग रोजगार के लिए पलायन करने पर मजबूर है। कल्याणकारी योजनाओं में लूट मची हुई है। जनता का कार्य नहीं हो रहा है। केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी की सरकार देश को फासीवादी रास्ते पर ले जा रही है। मोदी सरकार में संविधान और लोकतंत्र के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। भाजपा सरकार भारतीय संविधान के स्थान पर नागपुर से संचालित आरएसएस का संविधान लागू करना चाहती है। जिसे देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मोदी सरकार के खिलाफ आम जनता में गुस्सा व्याप्त है। आगामी लोकसभा चुनाव–2024 में भाजपा की विदाई तय है।

बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और नौजवान सभा ने भाजपा हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ का बिलासपुर में आगाज किया है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 14 अप्रैल 2023 से 15 मई 2023 संपूर्ण भारत भर में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी आभियान के तहत 18 अप्रैल 2023 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय वार्ड नंबर 43 बंसीलाल घृतलहरे नगर बूटापारा बिलासपुर में शाम 6बजे से आम सभा कर लोगों को जागरूक किया। सभा की अध्यक्षता वरिष्ठ भाकपा नेता ध्रुव धूरी ने की। सर्वप्रथम सभा को नौजवान सभा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत शर्मा ने संबोधित करते हुए देश में बढ़ती बेरोजगारी को नौजवानों के भविष्य के लिए खतरनाक बताया साथ ही सार्वजनिक इकाइयों का निजीकरण किए जाने पर केंद्र पर निशाना साधा एवं बेरोजगारी भत्ता और राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में लम्बे समय से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को राज्य सरकार परमानेंट करे की मांग की। एआईएफएफ के राज्य परिषद सदस्य संत निराला ने अपनी बात रखते हुए केंद्र सरकार को महंगाई बढ़ाने का जिम्मेदार ठहराते हुए जीवन उपयोगी आवश्यक दाल, चावल, आटा, कपड़ा व अन्य वस्तुओं पर जीएसटी

शेष पेज 10 पर...

मई दिवस 2023

वर्तमान समय में मजदूर वर्ग के समक्ष चुनौतियां

विद्यासागर गिरि

अंतर्राष्ट्रीय मई दिवस 2023 भारत में कठिन चुनौतियों के वर्ष के रूप में आयोजित होने जा रहा है। एटक कार्यकारिणी की लखनऊ बैठक में बड़े पैमाने पर मई दिवस आयोजन का आह्वान किया गया है। देश के सभी 10 केंद्रीय श्रम संगठनों एवं स्वतंत्र फेडरेशनों ने 2023 वर्ष को मजदूर वर्ग, किसान, आम जनमानस और देश हित के रक्षार्थ मजदूर विरोधी, जन विरोधी और देश विरोधी नीतियों वाली हुकूमत के खिलाफ सतत राष्ट्रव्यापी जनजागरण अभियान चलाने का आह्वान किया है।

महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर आयोजित मजदूरों के राष्ट्रीय कन्वेंशन में स्वीकृत घोषणा पत्र में अप्रैल से जुलाई 2023 तक देशभर में राज्य से जिला एवं सेक्टोरल स्तर पर संयुक्त कन्वेंशन आयोजित करने और 9 अगस्त के ऐतिहासिक भारत छोड़ो दिवस पर राज्य स्तरीय महापड़ाव आयोजित करने का उद्घोष किया है। केंद्रीय श्रम संघों के घोषित कार्यक्रमों और लक्ष्यों की पृष्ठभूमि में आयोजित मई दिवस 2023 का विशेष महत्व है। विगत वर्ष भारत के मजदूर वर्ग ने 28–29 मार्च 2022 दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर देश के सामने अपनी 12 सूत्री मांगों को रेखांकित किया था। मांगों में पहली मांग थी जो आज भी है कि चार लेबर कोड (श्रम संहिताओं) को समाप्त किया जाए। जब हम पहली मांग के विश्लेषण में जाते हैं तो समझ में आता है कि पिछले एक डेढ़ सौ वर्षों के संघर्ष से मजदूर वर्ग ने अपने बलिदानों के बाद जो कुछ अधिकार एवं सहूलियतें हासिल की थी और जिन्हें विभिन्न प्रावधानों के जरिये 44 केंद्रीय श्रम कानूनों में प्रतिष्ठापित किया गया, मोदी सरकार ने श्रम सुधारों के नाम पर 29 श्रम कानूनों को निरस्त कर उनके स्थान पर चार लेबर कोड बनाए और उन अधिकारों/सहूलियतों को कम/खत्म कर दिया। इस प्रक्रिया में मजदूरों के जिन अधिकारों का अतिक्रमण किया गया उनमें काम के घंटे संबंधी प्रावधान भी शामिल हैं। नए लेबर कोड में नियोक्ताओं को दिन में 12 घंटे काम लेने का अधिकार दे दिया गया है। दुनिया के मजदूर एक मई को मजदूरों के अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं जिनमें काम के आठ घंटे के कार्य दिवस के लिए अमेरिका के मजदूरों के 1 मई 1886 के ऐतिहासिक संघर्ष को याद किया जाता है जिसके आधार पर आईएलओ ने अपने पहले स्थापना सम्मेलन में पहला कन्वेंशन 8 घंटा काम का स्वीकार कर अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाया उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है। अमेरिका के मजदूर वर्ग ने अगस्त 1866 में नेशनल लेबर यूनियन की स्थापना कांफ्रेंस में आठ घंटे के कार्य दिवस के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया था। जिसमें संकल्प व्यक्त किया गया था कि अमेरिका के मजदूर आठ घंटे के कार्य दिवस को हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे।

19वीं सदी में अमेरिका एवं अन्य अनेक देशों में सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय को कार्य दिवस समझा जाता था। मजदूर वर्ग को 14 घंटे, 16 घंटे और कभी–कभी तो 18 घंटे भी काम करना पड़ता था। औद्योगिक क्रांति के शुरूआती वर्षों में न केवल मजदूरों से अधिक घंटे काम लिया जाता था बल्कि काम की स्थितियां भी बेहद खराब थी जिससे मजदूरों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता था। छोटे–छोटे बच्चों को भी कल–कारखानों में 12 घंटे और 16 घंटे काम करने पर मजबूर किए जाते थे। इन हालात के चलते अनेक मजदूर असमय ही मर जाते थे जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे–सभी शामिल थे। अमेरिका में ही नहीं, अन्य देशों में भी मजदूरों के सामने इसी तरह के अमानवीय स्थिति थी। अमेरिका ही नहीं अन्य सभी देशों में जहां मजदूरों से इतने अधिक घंटे काम लिया जाता था, इस अमानवीय परिस्थिति के खिलाफ हड़तालें हुईं। भले ही हड़तालों के कारण मजदूरों को हर बार भारी दमन का शिकार होना पड़ता था। परंतु हड़तालें होती ही रही। इस सिलसिले में आस्ट्रेलिया के भवन निर्माण मजदूरों का संघर्ष मजदूर इतिहास में काफी प्रसिद्ध है जिन्होंने नारा लगाया था– "आठ घंटे काम, आठ घंटे मनोरंजन और आठ घंटे आराम"। अपने लगातार संघर्ष के बल पर उन्होंने 1856 में ही आठ घंटे के कार्य दिवस के अधिकार को हासिल कर लिया था।

क्या यह विडम्बना नहीं थी कि एक तरफ तो आस्ट्रेलिया के मजदूर हैं जिन्होंने आठ घंटे के कार्यदिवस के अधिकार को 1856 में ही हासिल कर लिया था और दूसरी तरफ भारत के मजदूर हैं कि उसके लगभग 150 साल बाद उन्हें इस अन्याय का सामना करना पड़ रहा है कि श्रम कानूनों में संशोधन के नाम पर कार्य दिवस को बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया है? अभी–अभी 2023 में कनार्टक राज्य सरकार ने भारत सरकार के दबाव में एप्पल कंपनी से सांठ–गांठ कर राज्य के कारखाना अधिनियम में संशोधन कर कार्य दिवस 12 घंटा का प्रावधान किया है जो आईएलओ का कन्वेंशन नं. 1, जो भारत सरकार अनुमोदित किया है, उसका उल्लंघन है। एटक ने इसकी शिकायत आईएलओ में की है। क्या यह भारत के मजदूर वर्ग पर एक राक्षसी किस्म का हमला नहीं है? मजदूर वर्ग पर यह एक अकेला हमला नहीं है। श्रम कानूनों में संशोधन के नाम पर भारत के मजदूरों पर ऐसे कई हमले किए गए हैं। यहां तक कि उनके लिए ट्रेड यूनियनों का गठन करना और उनका सुचारू संचालन करना भी एक दुष्कर कार्य बन गया है। 1 मई 2023 को भारत का मजदूर वर्ग जब मई दिवस मनाएगा तो अभूतपूर्व ढंग से पैदा की जा रही चुनौतियों से मुकाबला हेतु रणनीतिक तरीके से एकताबद्ध कार्रवाई का आगाज किया जाना है। देश की सत्ता पर कब्जा जमा चुकी जन विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी नीतियों वाली हुकूमत के फासिस्टी तरीके से निजात पाने के लिए संकल्प लेकर आगे बढ़ने की दिशा में कारगर अभियान चलाकर 2024 के लिए पृष्ठभूमि बनाने का संकल्प लिया जाना है।

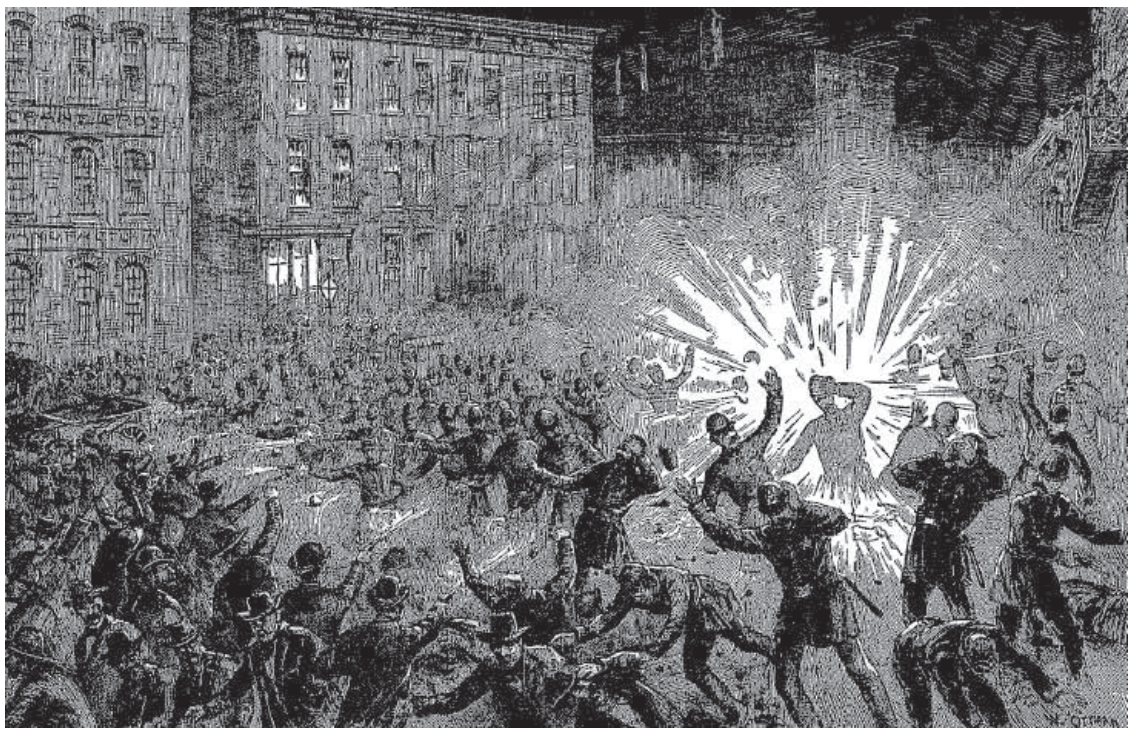

मई दिवस का इतिहास

अमेरिका में 1866 में नेशनल लेबर यूनियन की स्थापना कांफ्रेंस में 8 घंटे काम के समर्थन में प्रस्ताव पारित करने के साथ संकल्प व्यक्त किया गया कि अमेरिका के मजदूर 8 घंटे के कार्य दिवस को हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। उसी साल, पहले इंटरनेशनल की जेनेवा कांग्रेस ने भी 8 घंटे काम की मांग के संबंध में आवाज उठाई। पहला इंटरनेशनल विभिन्न देशों के मजदूर वर्ग का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसका संगठन स्वयं कार्ल मार्क्स ने किया था। पहले इंटरनेशनल की जेनेवा कांग्रेस ने 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग के संबंध में कहा: "कार्य दिवस की कानूनी सीमा एक ऐसी प्राथमिक शर्त है जिसके बिना मजदूर वर्ग के जीवन में सुधार एवं उनके उद्धार की दिशा में अन्य सभी कोशिशें निरर्थक हो जाएंगी। कांग्रेस मांग करती है कि 8 घंटे को कार्य दिवस की कानूनी सीमा तय किया जाए।" जेनेवा कांग्रेस के प्रस्ताव में कहा गया था कि "कार्य दिवस को सीमित करने की मांग उत्तरी अमेरिकी संयुक्त राज्य के मजदूरों की आम मांग का प्रतिनिधित्व करती है, अतः कांग्रेस इस मांग को समूची दुनिया के मजदूरों की आम घोषणा के रूप में रूपान्तरित करती है। अमेरिका के मजदूर वर्ग के राष्ट्रीय संगठन–फेडरेशन ऑफ ऑर्गनाईज्ड ट्रेड्स एंड लेबर यूनियन (जिसका बाद में नाम अमेरिका फेडरेशन ऑफ लेबर हो गया, ने 1884 में अपने राष्ट्रीय सम्मेलन में निर्णय किया कि एक मई 1886 को अमेरिका का मजदूर वर्ग 8 घंटे के कार्य दिवस के लिए आर–पार की लड़ाई शुरू कर देगा। उसने घोषित किया कि "1 मई 1886 से और उसके बाद 8 घंटे कार्य कानूनी तौर पर कार्य दिवस होगा"। इस आह्वान पर 1 मई 1886 को अमेरिका के लाखों मजदूर हड़ताल पर चले गए। दूसरे दिन भी हड़ताल रही, तीसरे दिन भी हड़ताल जारी रही।"

हड़ताल का सबसे बड़ा केंद्र शिकागो था। शिकागो में हड़ताल के तीसरे दिन म्कोर्मिक रीपर वर्क्स नामक औद्योगिक संस्थान के सामने मजदूरों की एक आम सभा चल रही थी जहां पुलिस ने मजदूरों पर हमला कर दिया। मजदूरों पर इस हमले का विरोध करने के लिए 4 मई को हे–मार्केट चौक पर एक जन सभा करने का फैसला किया गया। जन सभा शांतिपूर्वक चल रही थी और खत्म होने वाली ही थी। सभा में मौजूद लोगों की संख्या काफी कम थी। ठीक इसी समय किसी ने वहां मौजूद पुलिस बल के ऊपर बम फेंक दिया। किसी को नहीं पता बम किसने फेंका था। परंतु अटकलें लगती रही है कि पुलिस के लिए काम करने वाले किसी भड़काने वाले एजेंट ने ही यह काम किया था। बम विस्फोट में कुछ पुलिस वाले मारे गए। उसके बाद पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी जिसमें अनेक मजदूर मारे गए, अनेक जख्मी हुए। 8 लोगों को बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया जिनमें से तीन ही मौके पर मौजूद थे। उन पर मुकदमा चलाया गया और हत्या के मुजरिम करार दिया गया। इस मुकदमें के लिए जो जुरी बनाई

गई थी उसमें उद्योगपति एवं कारोबारी शामिल थे। उन्होंने उन्हें दोषी ठहरा दिया। उनके किसी कारनामे के लिए नहीं, क्योंकि बम विस्फोट के मामले में तो वह सभी के सभी निर्दोष थे। परंतु उन्हें उनके राजनीतिक एवं सामाजिक विचारों के लिए दोषी ठहराया गया। इसके खिलाफ अपीलें भी की गई। पर सभी अपीलें ठुकरा दी गई। इसके बाद 11 नवंबर 1887 को मजदूर नेताओं– पारसन्स, स्पाइस, एंगल और फिशर को फांसी दे दी गई। लुईस लिंग्ग ने सजा के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराते हुए फांसी की तारीख से पहली रात ही आत्महत्या कर ली। बाद में अमेरिका के मजदूर वर्ग ने मई दिवस के शहीदों–अल्बर्ट पारसन्स, एंगल, फिशर, स्पाइस और लुईस लिंग्ग की याद में शिकागो में एक स्मारक बनाया। स्मारक पर लिखा है: "वह दिन आएगा जब हमारी खामोशी उन आवाजों से अधिक ताकतवर होगी जिनका गला आज आप घोंट रहे हैं।" सचमुच उनकी खामोशी अत्यंत ताकतवर साबित हुई और उन्होंने जिस बात के लिए संघर्ष किया, आठ घंटे के कार्य दिवस के लिए उनका वह संघर्ष की ऐतिहासिक विजय हुई और अंततः आईएलओ के प्रथम कन्वेंशन में 8 घंटा का कार्य दिवस पारित कर वैश्विक बाध्यकारी कानूनी प्रावधान बनाये गये जो सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का वैश्विक आयोजन का फैसला 14 जुलाई 1889 को पेरिस में अनेक देशों के मजदूर नेताओं की एक बैठक हुई जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन–दूसरे इंटरनेशनल की स्थापना हुई (पहला इंटरनेशनल 1876 में भंग हो चुका था)। दूसरे इंटरनेशनल की इस स्थापना कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें लिखा गया कि: "इंटरनेशनल की यह कांग्रेस एक महान अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के आयोजन का फैसला करती है ताकि सभी देशों और सभी शहरों में एक तयशुदा दिन मेहनतकश अपनी सरकारों से मांग करें कि कार्य दिवस को कानूनी तौर से कम करके 8 घंटे का बनाया जाए; साथ ही कांग्रेस पहली कांग्रेस के अन्य फैसलों पर काम करने का फैसला भी करती है। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर दिसंबर 1888 में सेंट लुईस में अपने सम्मेलन में पहले ही 1 मई 1890 को प्रदर्शन का फैसला ले चुकी है, अतः अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के लिए भी इसी दिन को स्वीकार किया जाता है। विभिन्न देशों के मजदूरों को अपने–अपने देश के हालात को ध्यान में रखते हुए 1 मई को प्रदर्शन करने चाहिएं।"

दूसरे इंटरनेशनल के इस आह्वान पर दुनिया के अनेक देशों, विशेषकर यूरोप के देशों में 1 मई 1890 को मजदूरों के विशाल प्रदर्शन हुए और उस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाने का सिलसिला शुरू हो गया। आज दुनिया में हर कहीं मई दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है और अनेक देशों में और भारत के कुछ राज्यों में भी इस दिन सरकारी छुट्टी रहती है। भारत में मजदूर वर्ग के समक्ष गंभीर चुनौतियां दरअसल, आज भारत का मजदूर वर्ग के साथ पूरा देश एक ऐसे कठिन दौर से गुजर रहा है जैसा स्वतंत्रता के बाद तो क्या, स्वतंत्रता के पहले भी कभी नहीं रहा। मजदूर वर्ग के तमाम अधिकारों और एक वर्ग के तौर पर उनके सम्मान पर हमला हो रहा है। देश की आम जनता और देश की साझी विरासत भी तबाही के मार्ग पर है। यह चुनौतियां न सिर्फ हमारे देश के मजदूर वर्ग द्वारा भारत में अर्जित श्रम अधिकारों और संगठित ट्रेड यूनियन पर हमला है, बल्कि हमारे देश के शासन द्वारा वैश्विक स्तर पर हस्ताक्षरित व स्वीकृत अंतरराष्ट्रीय समझौतों, प्रस्तावों और निर्धारित अंतरराष्ट्रीय मानकों की अवहेलना कर उस पर भी बेशर्म हमलों का दौर चला रखा है। हमारे देश में आईएलओ के फंडामेंटल यानी मूल और सरकार द्वारा अनुमोदित बाध्यकारी कन्वेंशनों और आईएलओ का संविधान, जो सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी है और अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उसका भी हमारे देश की वर्तमान सरकार द्वारा खुला उल्लंघन किया जा रहा है। विश्व गुरु बनने की बात करने वाली हमारे देश की हुकूमत अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक, संयुक्त राष्ट्र संघ का सतत विकास लक्ष्य घोषणा, वैश्विक समझौतों, मानवाधिकार पर घोषित अंतरराष्ट्रीय घोषणा पत्र, आईएलओ का उत्कृष्ट कार्य त्रिपक्षीय समझौता आदि पर सरकार हस्ताक्षर कर उसके विपरीत आचरण का दोहरा मानदंड अपना रही है।

श्रम विरोधी मोदी सरकार की याराना पूंजीवादी कारपोरेट पक्षधरता वाली नीतियां आज पराकाष्ठा पर हैं। 44 श्रम कानूनों को समाप्त कर बनाए गए चार श्रम संहिता, जिसमें अनेकों प्रावधान और अंर्ततत्व अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों का खुला उल्लंघन है। कथनी में "श्रमेव जयते" और करनी में "श्रमेव क्षयते" का यह खतरनाक दौर श्रम क्षेत्र एक गंभीर चुनौतियां है। 2014 में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से उत्पन्न जन असंतोष पर सवार होकर और प्रतिवर्ष दो करोड़ नौकरियां देने, महंगाई रोकने, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का वादा करके सत्ता में आई मोदी सरकार अपने ही वायदों को जुमला बता चुकी है। काला धन रोकने के नाम पर की गई तबाही वाली नोटबंदी जो आम जनता और अर्थव्यवस्था पर कहर और अरबों रुपए के काले धन को चोर दरवाजे से सफेद करने का जरिया बनाया गया, जिसकी जांच आज तक नहीं हुआ। यह हुकूमत अपने 9 वर्षों के शासन में भारत की समृद्ध विरासत हो या आजाद भारत की उपलब्धियों, सबको एक तरह से ध्वस्त कर भारत के नींव और बुनियादों पर मर्मांतक हमला कर रही है। भारत में घृणा, द्वेष, धर्म उन्माद का वातावरण सृजित और प्रचारित कर भावनात्मक ढंग से जनमानस का ध्यान मूल मुद्दों से हटाने और सामाजिक मनोविज्ञान बदलने का कार्य किया जा रहा है। शासन प्रशासन के हर अंग प्रत्यंगो और संवैधानिक संस्थानों तक का नीचतापूर्ण दुरुपयोग कर जनतांत्रिक, नैतिक और संवैधानिक मूल्यों तक को ध्वस्त किया जा रहा है। यह याराना पूंजीवादी सरकार, कारपोरेट हित साधने हेतु सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जाने, समाज में घृणा, हिंसा, आतंक, डर, लोभ, लालच सहित किसी भी कुकर्मों को करने से परहेज नहीं कर रही है। अपने भ्रष्ट आचरण से संवैधानिक, सामाजिक, न्यायिक एवं विधि सम्मत मर्यादाओं और नैतिकता को तार–तार कर जो स्थितियां पैदा कर रही है वह देश के भावी पीढ़ी और समाज के लिए अभिशाप से कम नहीं है। भ्रष्टाचार की जीरो टोलरेंस की बात करने वाली यह सरकार भ्रष्ट आचरण में आकंठ डूबी है। फर्जी मुकदमें बनाना, कुख्यात भ्रष्टाचारियों को अपने दल में मिलाकर ईमानदार घोषित करना, विधायकों की खरीद एवं पैसे का खेल और अपने घपले घोटालों की जांच तक कराने से बेशर्मी पूर्वक इंकार कर सरकार एक तानाशाह जैसे शासन चला रही है। राफेल खरीद घोटाला हो या पनामा पेपर लीक मामले, पेगासस जासूसी हो या चुनावी लाभ हेतु पुलवामा हमला का राजनीतिक उपयोग, उसके पूर्व नोट बंदी और काले धन को शत–प्रतिशत सफेद करा देने के मामले, लाखों–हजारों–करोड़ों के सरकारी और पब्लिक सेक्टर के संस्थानों, हवाई अड्डे, पोर्ट, उद्योगों और प्राकृतिक खनिज संसाधनों को मामूली कीमतों पर अपने चहेते अडानी, अंबानी और टाटा, आदि जैसे को मामूली कीमतों पर सौंपने के घोटाले और लाखों करोड़ों के बैंक ऋण माफी और हेयरकट, हाल ही में उद्घाटित हिंडनबर्ग खुलासे का हजारों करोड़ों का अडानी महाघोटालों की जांच तक कराने के लिए यह हुकूमत तैयार नहीं है। मीडिया और संचार माध्यमों पर संपूर्ण नियंत्रण के सहारे धर्म की गंदी राजनीति कर विमर्श के मुद्दों में एक खास धर्म और धर्मावलंबियों के प्रति घृणा का प्रचार कर भारत के सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्ष संविधान से नींव को हिला रही है। इतना ही नहीं भारत के समृद्ध और वैज्ञानिक ढंग से लिखे गए इतिहास को पाठ्यक्रमों से हटाकर नई पीढ़ी और छात्रों को वास्तविक एतिहासिक ज्ञान से भी वंचित करने का अपराधिक कृत्य कर रही है। कुल मिलाकर फासिस्ट तरीके से चलाई जा रही शासन व्यवस्था और देश के सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्रों की संपदाओं को नीलाम कर देश बेचने जैसी स्थिति पैदा कर रही है जो अभूतपूर्व खतरनाक दौर का संकेत देता है।

अभी पुलवामा हमले के संदर्भ में जम्मू कश्मीर के तत्कालिक राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा किए गए खुलासे, भाजपा के महामंत्री द्वारा किए गए आर्थिक अपराध के खुलासे से बौखलाई सरकार पूर्व राज्यपाल के खिलाफ भी अपनी पालतू सीबीआई लगा दी है। यह न सिर्फ जनतांत्रिक मूल्यों और विरोध की आवाजों को नीचतापूर्ण तरीके से दबा रही है, षडयंत्रपूर्वक विपक्षियों पर हमले ही नहीं बल्कि शासन–प्रशासन और राज्य सत्ता के अंग प्रत्यंगों को और उसकी गरिमा तक को ध्वस्त करने में परहेज तक नहीं करती। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे टिप्पणियों और संवाद के बाद बीबीसी जैसे संस्थानों और स्कॉलरों और बुद्धिजीवियों और न्यायाधीशों पर भी हमलावर बन जाती है। हर मुद्दों को और अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए छद्म राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति का लबादा पहन अपना बचाव कर रही है। एक व्यक्ति जिसके वक्तव्य, जिसके ज्ञान और गरिमा, सत्य निष्ठा सब का सब नैतिक मूल्यों के विपरीत है। जिस व्यक्ति के अनैतिकता और दोमुंहेपन के अनेकों प्रमाणित तथ्य हैं, हृदय हीनता के रिकॉर्ड हैं, उसका महिमामंडन कर, आभासी सत्य सृजन कर पुनः सत्ता में आने के लिए किसी भी हद तक जाने का कार्य कर सत्ता शक्ति का दुरुपयोग कर कर रही है। यह पूरे देश और सभ्य समाज के लिए एक गंभीर चुनौती है। ऐसी चुनौती के काल में मई दिवस 2023 का आयोजन एक संकल्प का दिन है। यह संकल्प लेना है कि इस देश की जनता का जनाधिकार, जनतंत्र, संवैधानिक और नैतिक मूल्यो के हिफाजत के साथ–साथ राष्ट्र और राष्ट्र की गरिमा के हिफाजत के लिए ऐसे क्रूर फासीवादी शक्तियों को सत्ता से उखाड़ कर फेंका जाए। यह आज का परम कर्तव्य है। आइए 2023 के मई दिवस इस संकल्प के साथ मनाएं कि जनतंत्र, नागरिक अधिकार, श्रम अधिकार, मानवाधिकार, भारत का संविधान, नागरिक आजादी और सामाजिक सौहार्द और नैतिक मूल्यों की हिफाजत के लिए सत्ता में बैठे फांसीवादी सोच की शक्तियों को 2024 में सत्ताच्युत करने के लिए पूरी शक्ति से जुट जाएंगे और केंद्रीय श्रम संगठनों के 30 जनवरी, 2023 के घोषणापत्र के कार्यक्रमों को शत–प्रतिशत सफल किया जाएगा।

मई दिवस जिन्दाबाद!

अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जिन्दाबाद!!

दुनियाभर के मजदूरों एक हों!!!

कामरेड दुष्यंत ओझा की तृतीय पुण्यतिथि पर व्याख्यान माला

''अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समक्ष चुनौतियाँ''

जयपुरः भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व राज्य सचिव कामरेड दुष्यंत ओझा की तृतीय पुण्यतिथि पर पार्टी द्वारा उनके जन्म स्थान शाहपुरा (भीलवाड़ा) में व्याख्यान माला 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समक्ष चुनौतियां' विषय पर आयोजन राजकीय चिकित्सालय शाहपुरा ऑडिटोरियम में किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम पार्टी के राज्य सचिव नरेन्द्र आचार्य ने सम्बोधित करते हुए कहा कि देश के राजनैतिक हालात, लोकतंत्र, संविधान, धर्म निरपेक्षता, साम्प्रदायिक सौहार्द, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समक्ष गंभीर चुनौतियाँ हैं। इन चुनौतियों के खिलाफ कामरेड ओझा ने अपने राजनैतिक जीवन में कई संघर्ष किये थे, वे राज्य में साम्प्रदायिक सौहार्द के लिये साम्प्रदायिकता विरोधी आन्दोलन के अगुआ थे। वे विश्व शान्ति के लिये राज्य में शांति एकजुटता संगठन के माध्यम से हमेशा राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे। कामरेड ओझा ने एक पत्रकार, वकील, साहित्य प्रेमी, आदिवासियों, दलितों, किसानों, महिलाओं, छात्र –युवाओं, साहित्यकारों, कलाकारों के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई। राज्य के हितों शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति उनकी अपनी अलग भूमिका थी। वर्तमान में कामरेड ओझा के सिद्धान्तों, उनके संघर्षो की रोशनी से हमें प्रेरणा लेकर वर्तमान की चुनौतियों का मुकाबला करना होगा। कामरेड आचार्य ने इस अवसर पर विशेष रूप से उनके पुत्र डॉ. विवेक ओझा जो चैक गणराज्य में रहते हैं, जिन्होंने देश में आई विपदा कोरोना काल में अपने पिता के सिद्धान्तों, उनके कार्यो, संघर्षो को आगे बढ़ाने के लिये राज्य पार्टी के माध्यम से राजकीय चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज में 1 करोड़ रुपये की लागत के वेंटिलेटर भेंट किये और आज उनकी तृतीय पुण्य तिथि पर उनके जन्म स्थान शाहपुरा में 12.50 लाख की लागत का वेंटिलेटर राजकीय चिकित्सालय शाहपुरा (भीलवाड़ा) में जनता की सेवार्थ भेंट किया जा रहा है। डॉ. विवेक ओझा का राज्य पार्टी की ओर से हम आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि वो कामरेड दुष्यन्त ओझा के विचारों, उनके संघर्षो को आगे बढ़ाने के लिये पार्टी को हमेशा की तरह आगे भी सहयोग करते रहेंगे। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता कामरेड तारासिंह सिद्धू ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में ऐसे आयोजन होते रहने चाहिये। कामरेड सिद्धू ने कहा कि अपने जीवन में कामरेड दुष्यन्त ओझा के साथ लम्बे समय तक साथ में काम करने का मौका मिला। वे प्रखर राजनीतिक थे, उनके संबंध तमाम राजनैतिक दलों के नेताओं से थे। कामरेड ओझा हमेशा मानवीय मूल्यों, साम्प्रदायिक सौहार्द के साथ समाज में चेतना संचार का काम करते थे। आज देश में जो माहौल है, उसमें संविधानिक मूल्यों, लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समझ जो चुनौतियाँ है, इसे हमारी एकता के साथ मुकाबला करने की जरूरत है। इस अवसर पर शाहपुरा के कवि कैलाश मंडेला ने कामरेड ओझा के व्यक्तित्व व कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसके अलावा पार्टी के उदयपुर जिला सचिव सुभाष श्रीमाली, चित्तौड़गढ़ के पार्टी की साथी राधा भण्डारी आदि ने भी सम्बोधित किया। इस विचार गोष्ठी की अध्यक्षता डॉ. अनंत ओझा ने की, मंच पर उनकी पुत्री एकता सिखवाल, चिकित्सा अधिकारी डॉ. अशोक जैन रहे तथा संचालन भीलवाड़ा जिला पार्टी के सचिव कैलाश गहलोत ने किया। उसके पश्चात चिकित्सा अधिकारी डॉ. अशोक जैन को वेंटिलेटर सुपुर्द किया गया। राजकीय चिकित्सालय शाहपुरा के ऑडिटोरियम में उनके परिवार, वकील, पत्रकार, राजैतिक, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के साथ पार्टी के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के साथी भी शामिल रहे। अंत में दो मिनट का मौन रखकर करामरेड दुष्यंत ओझा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

भाकपा के जन अभियान को मिल रहा है व्यापक जन समर्थन

पेज 7 से जारी...

लगाने पर केंद्र सरकार की घोर निन्दा की और महंगाई, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार की जनविरोधी, छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष तेज करने का आह्वान किया।

भाकपा जिला सचिव पवन शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए किसानों और मजदूरों को एकजुट होकर केंद्र सरकार को कारपोरेट घरानों की कठपुतली राष्ट्रवादी सरकार करार दिया। केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए देश की अर्थव्यवस्था पर चिंता जाहिर की, साथ ही कारपोरेट घरानों के टैक्स माफी पर सवाल उठाया और देश में जातिवाद, संप्रदायवाद, गैर बराबरी, धार्मिक उन्माद बढ़ने पर केंद्र सरकार की फासीवादी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही वर्षो से काबिज लोगो को पट्टा और मकान बनाने के लिए 5 लाख रुपया देने की मांग की।

सभा में लोकप्रिय एमआईएस मेंबर सामाजिक कार्यकर्ता कांग्रेस के जुझारू नेता परदेशी राज जी (पाषर्द) की गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ।

आमसभा में मुख्य रूप से पवन शर्मा, ध्रुव कुमार धूरी, दिलीप धूरी, विक्रम शर्मा, पुनाराम धूरी, संत निराला, गोकुल चौहान, पावेल शर्मा, साधु राम धूरी, संतराम धूरी, मंतराम धूरी, रवि शर्मा बाबूलाल केवट आदि मौजूद थे।

ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा देशव्यापी जन जागरण पदयात्रा 14 अप्रैल से 15 मई 2023 तक करने का फैसला किया है। इसी तारतम्य में ग्वालियर में पदयात्रा जारी है।

कौशल शर्मा एडवोकेट, ग्वालियर जिला सह सचिव एवं राज्य कार्यकारिणी सदस्य भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मध्य प्रदेश ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि ग्वालियर में जन जागरण पदयात्रा के अगले चरण में 21 अप्रैल 2023 को पार्टी द्वारा नदी पार टाल मुरार ग्वालियर के इलाके में जन जागरण पदयात्रा कर सभा की जिसमें, भाजपा –हटाओ, देश – बचाओ, भाजपा – हटाओ, संविधान–बचाओ, भाजपा – हटाओ, लोकतंत्र–बचाओ के नारे के साथ पदयात्रा निकाली गयी। वक्ताओं ने कहा कि देश में केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की गलत नीति के कारण देश में बढ़ रही गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, सरकार द्वारा प्रायोजित सांप्रदायिक नफरत एवं जातिगत विभाजन, देश की जनता द्वारा बनाए गए सार्वजनिक संस्थानों को ओने पौने दाम में बड़े पूंजीपतियों को बेचने एवं अडानी के आर्थिक घोटाले की जांच जेपीसी गठित करने की मांग के अलावा अन्य समस्याओं से जनता को अवगत कराने के लिए पदयात्रा निकाली गई। जिसमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुषों ने भाग लिया।

25 अप्रैल

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा 14 अप्रैल से 14 मई 2023 तक देशव्यापी पदयात्रा भाजपा हटाओ–देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ के आव्हान के तहत ग्वालियर मध्य प्रदेश में जन जागरण पदयात्रा जारी है इसी तारतम्य में आज शहर ग्वालियर जिला ग्वालियर के विभिन्न इलाकों में पदयात्रा कर किला गेट चौराहा पर सभा की गई।

कौशल शर्मा एडवोकेट ग्वालियर जिला सह सचिव एवं राज्य कार्यकारणी सदस्य भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मध्य प्रदेश ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि नौ वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व मे पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालो से पैदा हुये जन असंतोष की लहर पर सवार होकर सत्तासीन हुई थी। चुनाव प्रचार के दौरान जनता को 'न खाउंगा न खाने दूंगा' के भ्रष्टाचार विरोधी नारे के साथ, हर साल दो करोड़ रोजगार, हर व्यक्ति को पंद्रह लाख रुपये, किसानों की आय दुगनी करने के सब्जबाग दिखाए गये थे। दावा 'सबका साथ सबका विकास का किया गया था' लेकिन अब जब मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल समाप्त होने को है, देश की मेहनतकश जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। देश मे सत्तर साल कुछ नही हुआ और जो कुछ हुआ वह पिछले नौ साल मे हुआ, यह दावा करने वाली सरकार की कुल उपलब्धि यह है कि देश के 80 करोड़ लोग पांच किलो राशन के लिए राशन दुकान के सामने लाइन लगाये खड़े हैं। रोजगार के अवसर बढ़ने की जगह घट गये हैं और मोदी जी पकौड़ा बेचकर रोजी रोटी कमाने की सलाह दे रहे हैं। पिछले नौ साल मे करीब बीस करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे ढकेल दिए गये हैं। आज गरीबी, बेरोजगारी, मंहगाई, सामाजिक सुरक्षा, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, के विश्व मानकों मे भारत सबसे निचले पायदान पर है और इसमे निरन्तर गिरावट दर्ज की जा रही है।

गाजीपुर (उत्तर प्रदेश)

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय जन अभियान, भाजपा हटाओ, देश, संविधान, जनता बचाओ के तहत देवकली ब्लॉक के अंतर्गत पहलवानपुर ग्राम मे लोगो के बीच परचा वितरण एवं सरकार की विफलता पर प्रकाश डालते हुए पार्टी राज्य कार्यकारिणी सदस्य अमेरिका सिंह यादव ने कहा कि वर्तमान सत्तासीन सरकार में, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी,चरम पर है। कानून व्यवस्था चौपट है। दलित, शोषित, पीड़ित लोगों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। बेटी, पढ़ाओ, बेटी बचाओ का नारा फेल हो गया है। खुद भाजपा के प्रभावशाली नेता के उपर अन्तराष्ट्रीय महिला पहलवानो द्वारा यौन शोषण का आरोप लगाते हुए, रिपोर्ट दर्ज करने की मांग को लेकर नई दिल्ली में धरना दिया जा रहा है। परन्तु माननीय प्रधानमंत्री एवं सरकार उस नेता को बचाने पर लगी है। इस पार्टी के अपराधी, माफिया दूध के धुले हैं। वहीं पर विपक्ष द्वारा सरकार की गलत नीतियों की आलोचना को देशद्रोह की संज्ञा दी जा रही है। यह सरकार तानाशाही के रास्ते पर चल रही है। इसलिए लोकतंत्र, संविधान को बचाने हेतु जनता को संगठित होकर आगामी चुनाव में भाजपा को सत्ता से बहर करना होगा। इस अभियान में ब्लॉक मंत्री बच्चेलाल, राजनाथ सिपाही, रामशुक्ला, प्रमोद प्रधान, दयाराम, गुड्डू आदि शामिल रहे। पार्टी फंड हेतु लोगो से अनाज भी मंगा गया।

भाकपा कर्नाटक में फासीवादी भाजपा को हराने के लिए प्रतिबद्ध

हरीश बाला

कर्नाटक भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण राज्य है क्योंकि यह लोकसभा में 28 सदस्य भेजता है। चुनाव आयोग ने 10 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है और वोटों की गिनती 13 मई को होगी। नामांकन दाखिल करने, जांच पूरी होने के बाद 224 निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है।

कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां चुनाव में जाति का दबदबा है। लिंगायत, वोक्कालिगा, ओबीसी, अल्पसंख्यक जैसे प्रमुख समुदाय खुद को एक राजनीतिक दल के रूप में पहचानते हैं और एक राजनीतिक दल खुद को इन जाति समूहों में से एक के प्रतिनिधि के रूप में पहचानता है। पैन–कर्नाटक क्षेत्रीय पार्टी के अस्तित्व में न आने का यही कारण है। जद (एस) चुनाव आयोग के अनुसार एक राज्य की पार्टी है, इसकी उपस्थिति और देवेगौड़ा परिवार का प्रभाव पुराने–मैसूर क्षेत्र तक सीमित है, जहां वोक्कालिगा राजनीतिक सत्ता पर हावी हैं। ज्यादातर चुनाव जातीय समीकरणों पर लड़े जाते हैं क्योंकि हर जाति के लोग चाहते हैं कि उनका प्रतिनिधि जीते।

लेकिन इस बार चुनाव का मुद्दा जाति के बारे में नहीं है। यह भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बुनियादी ढांचे की कमी, सांप्रदायिकता और अन्य सहित विभिन्न एजेंडे के बारे में है। कर्नाटक के लोग चाय की साधारण दुकान से लेकर ब्रांडेड कॉफी चेन तक हर जगह इन चीजों की चर्चा कर रहे हैं।

राज्य में बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को 40 प्रतिशत कमीशन सरकार के रूप में ब्रांडेड किया जा चुका है। आरोप है कि सरकार में मंत्री और रसूखदार लोग ठेकेदारों से 40 फीसदी कमीशन मांगते हैं ताकि उनके द्वारा किए गए काम के लिए फंड जारी किया जा सके। यह आरोप विपक्षी दलों का नहीं है। यह बात सरकारी ठेकेदार संघ ने प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से कही। एक संतोष पाटिल बेलगावी के ठेकेदार हैं। वह संघ परिवार के सक्रिय सदस्य हैं और एक ठेकेदार भी हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में पंचायत राज विभाग के तहत कुछ परियोजनाएँ कीं। बाद में उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया कि तत्कालीन पंचायत राज मंत्री ईश्वरप्पा उन पर 40 प्रतिशत कमीशन राशि का अग्रिम भुगतान करने का दबाव बना रहे थे और कि उसके बाद ही उनके बिलों को मंजूरी दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार प्रसिद्ध रूप से कहा था 'मैं नहीं खाउंगा, खाने दूंगा' लेकिन दुर्भाग्य से संतोष पाटिल के पत्र के जवाब में प्रधानमंत्री की चुप्पी के परिणाम यह हुआ कि संतोष पाटिल ने आत्महत्या की। इस घटना के बाद ईश्वरप्पा को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें आगामी विधानसभा चुनावों में लड़ने के लिए टिकट से वंचित कर दिया गया, क्योंकि उन्हें मैदान में उतारने से सत्ता विरोधी लहर बढ़ती।

राज्य सरकार की सभी भर्तियों में पारदर्शिता का अभाव है। लेक्चरर की भर्ती में घोटाले, पुलिस उपनिरीक्षकों, इंजीनियरों में योग्य उम्मीदवारों को प्रवेश से बाहर कर दिया गया है, केवल उन लोगों को नौकरी दी जा रही है जो लाखों रुपये का भुगतान करके इन नौकरियों को खरीद सकते हैं। थोक और खुदरा में रोजगार बेचने के लिए रोजगार कार्यालय एक मेगा मॉल बन गये हैं। इन नौकरियों को खरीदने के लिए सटोरियों और एजेंटों ने अच्छी तरह से सेटल कर लिया है। ये घोटाले भी दिन के उजाले में आ गए हैं। लेकिन इसमें शामिल अधिकारियों, सटोरियों, एजेंटों पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

राज्य में बेरोजगारी अभूतपूर्व हो गई है। कोई भी ग्रामीण बेरोजगारी को स्पष्ट रूप से देख सकता है क्योंकि बड़ी संख्या में युवा राज्य की राजधानी बेंगलुरु में डिलीवरी कामगारों, कैब चालकों जैसे अन्य छोटे–मोटे काम करने के लिए पलायन करते हैं। बसवराज बोम्मई इस सरकार को डबल इंजन सरकार कहते हैं। सही अर्थों में इस डबल इंजन सरकार द्वारा योजना के लिए मूंगफली आवंटित करके मनरेगा को पूर्ववत करने के अतिरिक्त प्रयासों का परिणाम ग्रामीण बेरोजगारी में हुआ है। नोटबंदी के कारण राज्य में लघु उद्योग बंद होने से लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। कोरोना लॉकडाउन ने बेरोजगारी के जख्मों पर भी मरहम लगा दिया है। साथ ही, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में शहरी रोजगार कन्नडों की तुलना में बाहरी लोगों द्वारा भरे जाते हैं।

ढांचागत विकास को लेकर भाजपा के दावे या तो आधे–अधूरे हैं या वोटों के तुष्टीकरण के लिए हैं। पीएम मोदी ने चुनाव घोषणा से कुछ दिन पहले बहुप्रचारित बेंगलुरु मैसूर राजमार्ग का उद्घाटन किया। लेकिन, उद्घाटन के कुछ दिनों बाद ही, जिस सड़क को विश्वस्तरीय होने का दावा किया गया था, उसमें एक दिन के लिए मामूली बारिश से ही पानी भर गया था। पिछले साल बेंगलुरू में बाढ़ उचित बुनियादी ढांचे की कमी के कारण आई थी। महादेवपुरा, मराठाहल्ली, कदीबीसनहल्ली, देवरबेसनहल्ली में बाहरी रिंग रोड क्षेत्रों के आईटी कॉरिडोर बारिश से भर गए। अनुमान लगाया गया था कि इस बाढ़ के कारण इन क्षेत्रों में आईटी फर्मों के लिए केवल दो दिनों में 250 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। भाजपा विभिन्न जातियों को खुश करने के लिए मूर्तियों के उद्घाटन को बुनियादी ढांचे के विकास के रूप में गिनाती है।

करावली कर्नाटक क्षेत्र जिसमें उत्तर कन्नड़ और दक्षिण कन्नड़ जिले शामिल हैं, वह संघ परिवार और भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे की प्रयोगशाला है। यहां हिजाब का मुद्दा बीजेपी ने शुरू किया था। भाजपा ने कर्नाटक के लोगों को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की। कर्नाटक में बहस और चर्चा केवल सांप्रदायिक मुद्दे थे। इसकी शुरुआत हिजाब पर प्रतिबंध के साथ हुई, इसके बाद हलाल मांस और फिर बीफ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस सरकार ने गौमांस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पारित किया है। इससे न केवल समाज के एक वर्ग को परेशानी हुई है बल्कि तथाकथित गोरक्षकों को भी लाइसेंस मिल गया है जो मुख्य रूप से गुंडे हैं। एक, इदरीस पाशा, को बेंगलुरु के बाहरी इलाके कनकपुरा में पुनीत कीरेनहल्ली के नेतृत्व में गोरक्षकों के एक समूह ने मार डाला था। गायों को बेचने के लिए केरल ले जाते समय गिरोह ने इदरीस पाशा और उनके सहयोगियों पर हमला किया था। गिरोह ने सथानूर पुलिस थाने के पास इदरीस पाशा की हत्या कर दी थी। मांड्या, कुनिगल जैसे स्थानों पर सामूहिक प्रार्थना के आयोजन के लिए कई ईसाई घरों पर हमला किया गया। कानून और व्यवस्था की स्थिति बदतर हो गई है क्योंकि गौरक्षकों और धर्म रक्षकों (वास्तव में धर्म रक्षकों) ने कानून को अपने हाथ में ले लिया है।

कर्नाटक के लोग भाजपा सरकार से तंग आ चुके हैं क्योंकि उसने आम आदमी के जीवन में सुधार के लिए कुछ नहीं किया है। बीजेपी सरकार के खिलाफ जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर है। बीजेपी मोदी भजन और जातिगत गणना के जरिए इसे दूर करने की कोशिश करती है। लेकिन, यह अनुमान लगाया गया है कि यह रणनीति पीछे हट जाएगी। राज्य में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कमी आई है। लोग सवाल कर रहे हैं कि मोदी चुनावों के दौरान बार–बार राज्य का दौरा क्यों कर रहे हैं जबकि बाढ़ और सूखे के समय उन्हें राज्य का दौरा करने का समय नहीं मिला। इस वाजिब सवाल का बीजेपी कार्यकर्ताओं के पास कोई जवाब नहीं है। लिंगायत वोट बैंक पर भाजपा की निर्भरता को भी झटका लगेगा क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी जैसे लोकप्रिय लिंगायत चेहरे भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं।

भाकपा की भूमिका

कर्नाटक में वामपंथी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक ताकतों के साथ हाथ मिलाने के लिए पिछले सितंबर में विजयवाड़ा में आयोजित पार्टी कांग्रेस द्वारा अपनाई गई लाइन के अनुसार, भाकपा ने चुनाव की घोषणा से कई महीने पहले कांग्रेस के साथ बातचीत शुरू की थी। भाकपा ने सात सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इन सीटों पर कांग्रेस के साथ दोस्ताना मुकाबला होगा। पार्टी ने बागेपल्ली में भाकपा (मा) और मेलुकोटे में सर्वोदय पक्ष के दर्शन पुत्तनैया को समर्थन दिया है, दोनों जीत की स्थिति में हैं। शेष 215 सीटों पर भाकपा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवारों को समर्थन दिया है। यह भाजपा विरोधी वोटों के बंटवारे से बचने के लिए है, जिससे भाजपा को फायदा होगा। भाकपा राज्य सचिव साथी सुंदरेश और कर्नाटक के कांग्रेस प्रभारी श्री रणदीप सुरजेवाला ने 23 अप्रैल 2023 को बेंगलुरु में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस समझ की घोषणा की थी। कर्नाटक में सांप्रदायिक और फासीवादी भाजपा को हराने के लिए भाकपा की प्रतिबद्धता और संकल्प पार्टी द्वारा लिए गए निर्णय में परिलक्षित होता है। भाकपा की इस उदारता की बुद्धिजीवी, प्रगतिशील विचारक और कार्यकर्ता सराहना कर रहे हैं।

भाकपा के समर्थन और अभियान के साथ, कांग्रेस 13 मई को वोटों की गिनती के बाद सरकार बनाने के लिए तैयार होगी।

कामरेड राम लाल के निधन पर भाकपा में शोक की लहर

बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश): भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने वरिष्ठ नेता कामरेड राम लाल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। कामरेड रामलाल बिलासपुर जिला के ऋषिकेश गांव के निवासी थे। बीते बुधवार 19 अप्रैल को उनका देहांत हो गया था। वे 75 वर्ष के थे। वे पिछले कुछ वर्षों से अस्वस्थ चल रहे थे।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के पूर्व सदस्य देशराज ने बताया कि आगामी रविवार 23 अप्रैल को उनके निवास स्थान ऋषिकेश में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एक शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अनेक नेता शामिल होंगे वहीं अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए उपस्थित रहेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व राज्य सचिव एवं बिलासपुर के वरिष्ठ नेता वसुदेव बसु ने कहा कि रामलाल एक सच्चे वामपंथी पुरोधा थे। वे वैचारिक तौर पर प्रतिबद्ध होने के साथ–साथ ताउम्र मजदूरों एवं कर्मचारियों के हितों की लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने बताया कि कामरेड रामलाल लोक निर्माण विभाग से अधीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। अपने सेवाकाल के दौरान कर्मचारियों के शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए उन्हें सरकार की ओर से सेवाओं से वंचित कर दिया गया था जोकि एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद पुनः बहाल कर दी गई थी। बसु ने बताया कि सेवानिवृत्ति के पश्चात वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बिलासपुर इकाई के सचिव के तौर पर अनेकों वर्षों तक पूरी सक्रियता से काम करते रहे। उनकी अगुवाई में पार्टी की ओर से पूरे जिला भर में जन जागरण अभियान को पूरी सफलता के साथ चलाया गया था।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव भाग सिंह चौधरी, सहसचिव प्रशांत मोहन एवं नरेश घई, पूर्व विधायक एवं अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य महासचिव के के कौशल, पूर्व अध्यक्ष हरदेव सिंह, एटक के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश चंद्र भारद्वाज, नानक चंद शांडिल, टी आर भारद्वाज, शशि पंडित, युवा नेता प्रवेश चंदेल, रामलोक ठाकुर, हिमाचल नारी सभा की नेता मीरा शर्मा आदि ने कामरेड रामलाल के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है।

उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त एवं न्यायिक प्रणाली पर हमला

आजमगढ़: (उत्तर प्रदेश) 16 अप्रैल 2023 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आजमगढ़ की जिला काउंसिल की एक दिवसीय बैठक दुर्बली राम की अध्यक्षता में माहुल स्थित केआरडी इंटर कॉलेज में संपन्न हुई। इस बैठक में युवा अधिवक्ता जितेंद्र हरि पांडेय को जनपद आजमगढ़ का जिला सचिव चुना गया। इसके साथ ही 21 सदस्यों की जिला कार्यकारिणी का चुनाव हुआ जिसमें चंद्रमोहन यादव व मंगल देव यादव को सहायक जिला मंत्री चुना गया। काउंसिल की बैठक में पयर्वेक्षक भाकपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व पूर्व राज्य सचिव डॉ. गिरिश शर्मा, उत्तर प्रदेश राज्य सचिव अरविंद राज स्वरूप, राज्य सचिवमंडल एवं राष्ट्रीय परिषद सदस्य, पूर्व विधायक इम्तियाज अहमद प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। नेताओं ने 15 अप्रैल की रात फूलपर मिजवां कैफी आजमी के मकान फतेह मंजिल में गुजारी। 16 अप्रैल की सुबह नेताद्वय ने कैफी आजमी, शौकत आजमी, फतेह हुसैन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नारे लगाए। कैफी आजमी के सपनो को हम मंजिल तक पहुंचाएगे, कामरेड कैफी आजमी को लाल सलाम के नारे से फतेह मंजिल गूंज उठी।

11 बजे दिन में केआरएफ इंटर कॉलेज में जिला काउंसिल की बैठक की शुरुआत हुई। डॉ. गिरीश शर्मा ने पार्टी के राष्ट्रीय महाधिवेशन की रिर्पोट के साथ ही प्रदेश एवं देश की वर्तमान परिस्थितियों पर विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने कहा की पुलिस अभिरक्षा में और रिमांड पर लिए गए चर्चित आरोपी भाईयों की प्रयागराज में सुनियोजीत षड्यंत्रपूर्वक हत्या को न्याय और न्यायिक प्रणाली पर गहरा हमला बताया। उत्तर प्रदेश में कानून और कानून का शासन छिन्न–भिन्न कर दिया गया है। मार देंगे, ठोक देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, की भाषा कोई और नहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया बोल रहा है। इन बातों से सरकार प्रायोजित भय और दमन के आतंक का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। एक तबके पर निर्मम जुल्म की ये वारदाते उन भोले भाले नागरिकों को भाजपा का वोट बैंक बनाए रखने की साजिश है। जिनको संघ परिवार ने साजिश के तहत तात्कालिक तौर पर अपने प्रभाव में ले लिया है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि लखीमपुर में किसानों पर जीप चढ़ा देने वाले भाजपा के गृह राज्यमंत्री के बेटे, कानपुर में मां बेटी के हत्यारे, और उन सजातीय सहधर्मी माफिया सरगनाओ को कब मिट्टी में मिलाया जायेगा। जिसकी सूची मीडिया और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

भाकपा राज्य सचिव अरविंद राज स्वरूप ने कहा कि ये संयोग है या प्रयोग, पुलवामा कांड में प्रधानमंत्री की घृणित भूमिका के खुलासे से मचे तूफान के बीच प्रयागराज की घटना को अंजाम दिया गया। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसी ज्वलंत समस्यायों पर पर्दा डालने का भी यह एक सुनियोजित प्रयास है। ऐसी घटनायें कानून व्यवस्था के विनष्ट होने का स्पष्ट सबूत है। जिसकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की रक्षा के लिए निर्धारित मशीनरी के ऊपर आती है। उस जिम्मेदारी की पहल की जानी चाहिए और डीजीपी को हटाया जाना चाहिए। नहीं तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया को त्याग पत्र देना चाहिए।

राज्य सचिवमंडल सदस्य, पूर्व विधायक इम्तियाज अहमद ने कहा कि देश और प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल को गर्म करने के लिए हवा दी जा रही है। एक जाति से दूसरी जाति को और एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। निषेधाज्ञा और उसके प्रावधानों से भी आगे बढ़कर सरकार द्वारा दी जा रही धमकियों से लोकतांत्रिक और देशभक्त ताकतें डरेंगी नही और वामदल मिल जुल कर आवाज उठाएंगे। उत्तर प्रदेश किसान सभा के अध्यक्ष इम्तियाज बेग और पार्टी राज्य कार्यकारिणीय सदस्य हामिद अली ने भी पार्टी और संगठन के प्रति महत्वपूर्ण विचार रखे । जिला काउंसिल की बैठक में जिला मंत्री व जिला कार्यकारिणीय के चुनाव के बाद बैठक के समापन के समय नव निर्वाचित जिला सचिव जितेंद्र हरि पांडेय ने सभी के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा की वर्तमान समय बहुत चुनौती पूर्ण है। आजमगढ़ की पार्टी उत्तर प्रदेश के सबसे बडी पार्टी है। आजमगढ़ की पार्टी का इतिहास देश और दुनिया के अंदर राहुल सांकृत्यायन, जय बहादुर सिंह, डॉ.जेड ए अहमद, झारखड़े राय, कामरेड कैफी आजमी के नाम से जाना जाता है। हमे पार्टी ने जो दायित्व सौंपा है, हम पार्टी संगठन के विस्तार और आंदोलनों में वफादारी और ईमानदारी से अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे।

किसानों पर कहर बरपा रही हैं नोएडा विकास की योजनायें

नियमानुसार मुआवजा देने में अटकाये जा रहे हैं रोड़े

डॉ. गिरीश

ग्रेटर नोएडा/लखनऊ, 24 अप्रैल, 2023, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण किसानों को वर्षो से जबरिया लूट रहा है। इससे वहाँ के किसान बेहद नाराज हैं। अपनी जमीनों के कानून सम्मत मुआवजे के लिये वे हर मुमकिन तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन डबल इंजन की सरकारें उनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। वे अपने ही बनाए कानून को लागू करने से मुकर रही हैं। ये किसानों के साथ बड़ा छल है।

लंबे समय से किसान अपने हित में सही फैसले का इंतजार कर रहे थे। मगर शुक्रवार को हुई बोर्ड बैठक में मुआवजे के रेट्स में मामूली वृद्धि की गई है।

नए भूमि अधिग्रहण कानून को लागू हुए 9 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने नए कानून के लागू होने के बाद वर्ष 2014 में मुआवजा वृद्धि की थी। जिस समय नया कानून लागू हुआ था, उस वक्त 1560 रूपए प्रति वर्ग मीटर मुआवजा दर थी। नए कानून के अनुसार प्राधिकरण को सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा देना चाहिए था। वर्तमान में इस कानून के अनुसार मुआवजा दर कम से कम 24 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर होनी चाहिए।

यह है फार्मूला:

जब नया भूमि अधिग्रहण कानून लागू हुआ तो सर्किल रेट और प्राधिकरण की मुआवजा दर लगभग बराबर थीं, जो 1560 रूपए थीं। कानून में कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में सर्किल रेट से चार गुणा मुआवजा दिया जाएगा। लिहाजा, तब अथॉरिटी को मुआवजा दर 6200 रुपये प्रति वर्ग मीटर घोषित करनी थी। परंतु प्राधिकरण ने किसानों के साथ छल करते हुए मुआवजा राशि में मात्र 940 रूपए की वृद्धि करके 2500 प्रति वर्ग मीटर किया था। इस तरह मुआवजा वृद्धि जहां चार गुना होनी थी, वहां दोगुना से भी कम हुई। इतना ही नहीं, प्राधिकरण ने नोटिफाइड 202 गांवों में ग्राम पंचायत खत्म करवा दीं। जिससे गांवों को शहर घोषित करने में कानूनी अड़चन ना आए और प्राधिकरण को सर्किल रेट का 2 गुना मुआवजा ही देना पड़े। प्राधिकरण ने साजिश करते हुए पिछले 9 वर्षो में गांवों की जमीनों के सर्किल रेट नहीं बढ़ने दिए हैं।

किसानों ने धोखे का आरोप लगाया:

किसान आरोप लगा रहे हैं कि अथॉरिटी ने हमारे साथ हमेशा धोखा किया है। किसान को सर्किल रेट से 2 या 4 गुना तो छोड़िए बाजार भाव से भी वंचित कर दिया गया। क्षेत्र के गांवों में कॉलोनाइजर 6000 से लेकर 15000 प्रति वर्ग मीटर की दर से जमीनों की खरीद कर रहे हैं। इस तरह बाजार भाव 6000 से कम नहीं है। नए कानून के अनुसार गांवों में 4 गुना मुआवजा 24000 रुपये प्रति वर्ग मीटर होता है। जिसकी मांग किसान लंबे समय से कर रहे हैं। उन्होने 24 मार्च को धरने– प्रदर्शन के बाद मुख्य कार्यपालक अधिकारी से बातचीत की। बातचीत में सीईओ रितु माहेश्वरी ने पर्याप्त मुआवजा वृद्धि करने का वादा किया था, परंतु शुक्रवार को हुई 129वीं बोर्ड– बैठक में मुआवजे में मात्र 375 रुपये की हास्यास्पद वृद्धि करके किसानों का मजाक उड़ाया गया है। जबकि प्राधिकरण ने इसी दौरान अपनी आवासीय, संस्थागत और औद्योगिक भूखंडों की आवंटन दरों में बेतहाशा वृद्धि कर ली है।

यहां उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण ग्राम कैलाशपुर, खेड़ी भनौता, सुनपुरा और अन्य गांवों के किसानों से अत्यंत कम दरों पर भूमि की खरीद कर रहा है। वहां पर इस मामूली मुआवजा वृद्धि से भारी नाराजगी फैल गई है। वे उद्वेलित हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं। नए कानून के अनुसार सर्किल रेट से 4 गुना मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसान तब तक आंदोलनरत रहेंगे जब तक कि उनकी समस्या हल नहीं हो जाती हैं।

भाकपा ने नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने की मांग की

पटना, 16 अप्रैल, 2023: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिवमंडल ने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग की है। सचिवमंडल ने कहा है कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से कोई सलाह नहीं ली गयी है।

भाकपा राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने कहा कि नई शिक्षक नियमावली 2023 सातवें चरण के शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों और वर्षो से बिहार सरकार में अपनी सेवा दे रहे नियोजित शिक्षकों के लिए निराश करने वाला है। सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों को इस प्रक्रिया से मुक्त रखा जाना चाहिए और उन्हें पुराने तरीके से नियोजित किया जाना चाहिए। सरकार ने 2019 में एसटीईटी परीक्षा को एक प्रतियोगी परीक्षा के बतौर आयोजित किया था, लेकिन बाद में वह उसे महज पात्रता परीक्षा कहने लगी। इसके कारण सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों में पहले से ही काफी आक्रोश है। इस बीच सीटीईटी–एसटीईटी–बीटीईटी की और परीक्षाएं भी ली गई है। नई शिक्षक नियमावली 2023 में बीपीएससी द्वारा परीक्षा लेने और शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिए जाने का प्रावधान है। शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिए जाने का निर्णय अच्छा कदम है, लेकिन विगत कई वर्षो से स्कूलो में कार्यरत नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा नहीं दिया जाना कहीं से जायज नहीं है। नियमावली में यह प्रावधान है कि सरकारी कर्मी का दर्जा हासिल करने के लिए नियोजित शिक्षकों को भी यह परीक्षा पास करनी होगी। नियोजित शिक्षक को परीक्षा से अलग रखना चाहिए और अधिसूचना के माध्यम से ही उसे राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए। क्योंकि नियोजित शिक्षक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण हैं। बीपीएससी से परीक्षा लेने के बाद भी शिक्षकों को नियमित शिक्षक की भांति वेतनमान और सेवा शर्त की व्यवस्था करने का मामला स्पष्ट नहीं है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मांग है कि नियोजित शिक्षकों के पूर्ण समायोजन के साथ पुराने शिक्षकों की भांति सेवा शर्त और वेतनमान दिया जाए तथा सीटेट/एसटीईटी/टीईट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सातवें चरण में नियुक्ति के बाद बीपीएससी द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ किया जाये।

भाजपा के धनबल से दूषित हो गया है भारतीय चुनावों में बराबरी का खेल

नित्य चक्रवर्ती

चुनावी बॉन्ड की 26वीं किश्त 3 अप्रैल से बिक्री पर रखी गयी है और यह 12 अप्रैल तक जारी रहेगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई को होने हैं। चुनावी बॉन्ड के प्रमुख लाभार्थी, इससे मिले धन का पूरा उपयोग करने की स्थिति में होंगे जो इस महत्वपूर्ण राज्य के चुनाव प्रचार और अन्य खर्चों के लिए बांड से हुई आय से उपलब्ध होगा। भाजपा के पास बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधन हैं, लेकिन कुछ अतिरिक्त का हमेशा स्वागत है, खासकर कर्नाटक चुनावों के बाद जहां लालची विधायकों के फर्श को पार करने में नकदी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

चुनावी बॉन्ड की 25वीं किश्त के मामले में नरेंद्र मोदी सरकार ने मूलभूत नैतिकता का उल्लंघन किया तथा पिछले साल 7 नवंबर को चुनावी बॉन्ड योजना के नियमों में हड़बड़ी में संशोधन किया तथा अतिरिक्त पंद्रह दिनों के लिए बिक्री की अनुमति दी गयी, एक वैसे समय में जब राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में चुनाव होने थे।

मूल चुनावी बॉन्ड योजना, 2017 के विरूद्ध याचिका पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और अगली सुनवाई इसी सप्ताह होने की उम्मीद है।इस 2017 अधिनियम के प्रावधानों को कानूनी विशेषज्ञों द्वारा पहले ही चुनौती दी जा चुकी है और यहां तक कि चुनाव आयोग ने भी कुछ प्रावधानों के बारे में संदेह व्यक्त किया है। चुनावी बॉन्ड की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने वाले वकील बॉन्ड के आगे चलन पर रोक चाहते थे, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद के लिए उपलब्ध हैं। आम चुनाव के वर्षो में अतिरिक्त 30 दिनों की विंडो की अनुमति है। अब नवीनतम संशोधन के माध्यम से, केंद्र ने पिछले साल हिमाचल और गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले नवंबर 2022 में एक और किश्त की अनुमति दी ।निर्धारित बिक्री इस साल 19 जनवरी से 28 जनवरी तक हुई थी ।जुलाई 2022 की बिक्री में, चुनावी बन्ड के माध्यम से कुल रु.10,246 करोड़ आये थे ।अक्टूबर 2022 के चंदे का आंकड़ा अभी उपलब्ध नहीं है लेकिन 2020–21 वित्तीय वर्ष के आंकड़े बताते हैं कि भाजपा को वित्त वर्ष के दौरान जुटाये गये कुल धन का 75 प्रतिशत हिस्सा मिला।

जनवरी 2018 में चुनावी बांड की बिक्री शुरू होने के बाद से पिछले पांच वर्षो में, भाजपा ने कर्नाटक, और मध्य प्रदेश में राज्य सरकारों को अस्थिर करने में हजारों करोड़ रुपये खर्च किए हैं और गोवा और मणिपुर में सरकार बनाने के लिए विधायक खरीदे हैं। महाराष्ट्र में, यह दिन के उजाले की तरह स्पष्ट था कि जुलाई 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना से एकनाथ शिंदे समूह के दल–बदल को सुनिश्चित करने के लिए भारी धन जुटाया गया था।

इसके बाद वहां शिंदे–भाजपा की सरकार बनी ।विपक्षी सरकारों को अस्थिर करने के इन सभी कदमों में, भाजपा ने कारपोरेट चंदे, चुनावी बॉन्ड के पैसे और विदेशी चंदे के माध्यम से जुटाये गये अपने विशाल उपलब्ध धन का उपयोग किया। कर्नाटक में, वर्तमान भाजपा सरकार को 40 प्रतिशत सरकार के रूप में जाना जाता है क्योंकि सभी निजी अनुबंधों के लिए ठेकेदारों को संबंधित भाजपा नेताओं को 40 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होता है।

इसी तरह, पांच चुनावी ट्रस्टों ने मिलकर 2021–22 में भाजपा को 481 करोड़ रुपये से अधिक के अपने कुल योगदान का 72 प्रतिशत वितरित किया, जबकि कांग्रेस ने किटी का मात्र 3.8 प्रतिशत हिस्सा साझा किया।

बॉन्ड या पोल ट्रस्ट से फंडिंग भाजपा के लिए एकतरफा रास्ता है क्योंकि चंदा देने वाली कंपनियां केंद्र में सत्ताधारी पार्टी को नाराज कर आईटी विभाग, सीबीआई या ईडी के माध्यम से कार्रवाई को आमंत्रित नहीं करना चाहती हैं। यह स्पष्ट था क्योंकि राहुल गांधी के साथ बातचीत के बाद बजाज परिवार के वंशज राजीव बजाज केंद्रीय एजेंसियों के हमलों से आशंकित थे।

भारतीय कारपोरेटों में यह डर इस कदर हावी है कि औद्योगिक घरानों के नौजवान वंशज जो भाजपा को पसंद नहीं करते और भविष्योन्मुखी हैं, वे भी चुप रहते हैं क्योंकि वे केवल कुछ उदारवादियों के लिए अपनी कंपनियों के भविष्य को जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं हैं।

शुद्ध परिणाम यह है कि चुनावों में कोई समान अवसर नहीं है। भाजपा विपक्षी दलों की तुलना में दस गुना से अधिक पैसा खर्च करने की स्थिति में है। इसके पास जरूरत पड़ने पर दलबदल कराने के लिए एक विशाल राजनीतिक युद्ध कोष है।

मोदी शासन के पिछले नौ वर्षो में, भारतीय कारपोरेट क्षेत्र में धन का असामान्य संकेन्द्रण हुआ है। हाल के एक अध्ययन से पता चलता है कि भारत की बीस सबसे अधिक लाभदायक फर्मो ने 1990 में कुल कारपोरेट मुनाफे का 14 प्रतिशत, 2010 में 30 प्रतिशत और 2019 में 70 प्रतिशत अर्जित किया।

इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी के शासन के पहले पांच वर्षो के दौरान कुछ कारपोरेट घरानों में धन के संकेंद्रण में तेजी से उछाल आया था। पिछले चार वर्षो में इस प्रक्रिया को और बल मिला होगा। विपक्षी दलों को भारतीय क्रोनी पूंजीपतियों और मोदी शासन के बीच इस लेन–देन पर ध्यान देना होगा और इस बात की जांच की मांग करनी होगी कि इस दीर्घकालिक व्यवस्था के तहत बड़े कारपोरेट कैसे सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा को फंडिंग कर रहे हैं। चुनावी बांड योजना में नवीनतम संशोधन भाजपा की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वह विपक्ष को चुनाव में बराबरी का मौका न देकर पंगु बना देने पर उतारू है।

सर्वोच्च न्यायालय अपनी अगली सुनवाई में इस बात पर विचार करेगा कि क्या केंद्र सरकार की 2018 की चुनावी बॉन्ड पेश करने की योजना को दी गयी चुनौती को अदालत की पांच–न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए? एक खंडपीठ, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा शामिल हैं, ने इसी उद्देश्य के लिए मामले को 13 अप्रैल को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।

केंद्र सरकार ने पिछली सुनवाई में अपना जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगा था। पीठ इस मामले को अंतिम निस्तारण के लिए दो मई को सूचीबद्ध करने पर विचार कर रही थी। हालांकि, याचिकाकर्ताओं में से एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की ओर से वकील शादन फरासत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और राजनीतिक दलों के फंडिंग पर पड़ रहा है।

एक एनजीओ याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने जवाब देने में देरी करने की सरकार की आदत पर कड़ी आपत्ति जतायी और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अदालत से तत्काल सुनवाई का आग्रह किया। यह अब सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों पर निर्भर है कि वे भारतीय लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें। यह संसदीय लोकतंत्र के जीवंत कामकाज के हित में होगा यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बांड योजना पर याचिका के अंतिम निस्तारण तक अंतरिम रोक लगा दे। (संवाद)

कामरेड महादेव नारायण टंडन स्मृति व्याख्यान

असहमति के विचारों के बिना संभव नहीं है, बेहतर दुनिया का बनना

आगराः माथुर वैश्य सभागार में आयोजित स्वतंत्रता सेनानी कामरेड महादेव नारायण टंडन स्मृति बीसवां व्याख्यान में बोलते हुए प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता और कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि जब हम विचारों की आजादी के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि हम किसी बहुत इंटेलेक्चुअल सी चीज पर बात कर रहे हैं, लेकिन विचार सिर्फ बुद्धिजीवी तबके से सम्बद्ध ही नहीं हैं। विचार सिर्फ साहित्य, कविता, दर्शन, नीति और धर्म ग्रंथों का मामला नहीं हैं। ये हम सबसे जुड़े हैं। हम सब अपने विचारों के आधीन हैं। हम चाह कर भी उन्हें बदल नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो हम में से कुछ लोग अपनी अपनी दिलचस्पी के हिसाब से बुद्ध, गांधी, मार्क्स, विवेकानंद, रामकृष्ण, मुहम्मद या जीसस जैसे हो गए होते। पर कमाल की बात है, कि हम अपने विचार किसी भी तरह मनचाहे ढंग से बदल नहीं सकते। डिप्रेशन में चले जाइए, तो निकलना मुश्किल पड़ता है। प्रेम हो जाए तो क्या हम अपने विचारों को नियंत्रित कर पाते हैं? अब जब हम खुद ही अपने विचार बदल नहीं सकते तो भला सरकार, धर्म या बड़ी बड़ी ऑथोरिटीज कैसे हमारे विचारों को नियंत्रित कर सकती हैं। ये नियंत्रण किसी बीमारी की तरफ भी ले जा सकते हैं और क्रान्ति की तरफ भी। विचारों का दमन पूरे व्यक्तित्व में कंफ्लिक्ट पैदा कर देता है।

जब मानव समाज में आपसी सामंजस्य के लिए नियम कानून बनाने की जरुरत पड़ी, तो कुछ बातें नैतिक मानी गई, कुछ अनैतिक। जो बाद में कानूनी और गैर कानूनी बन गयीं। लेकिन कमाल की बात वोटिंग राईट्स भी नहीं थे, वो बाद में देशों की मुखिया बनीं। जिन्हें अमेरिका में अछूत माना गया, वो बाद में वहाँ के राष्ट्रपति बन गए और ये सब जो बदला, वो किसने बदला। उसने, जो पुरानी व्यवस्था से सहमत नहीं था। अगर सही गलत की जो परिभाषा दुनिया में आज के पांच सौ साल पहले जैसी थी, आज उससे अलग है। तो ये मान कर चलिए कि आने वाले पांच सौ साल बाद भी ये दुनिया ऐसी नहीं रहेगी और इसे वो बदलेंगे, जो आज की परिभाषाओं से असहमत हैं।

अगर हम चाहते हैं, कि दुनिया बेहतर बनती रहे, बदलती रहे, तो असहमति के विचारों के बिना संभव नहीं है।

डॉ. जितेंद्र नारायण टंडन, सुप्रसिद्ध बालरोग विशेषज्ञ ने अपने पिता की स्मृति में आयोजित इस व्याख्यान में उनको स्मरण करते हुए कहा कि आजादी के साथ ही हमारी विचार की आजादी ही मनुष्यता की पहचान है वो विचार की आजादी है जो लगातार अपने नए सोपानों को तय करती है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता देश के जाने माने गीतकार डॉ. सोम ठाकुर जी ने की।

भाकपा द्वारा इस व्याखान का यह बीसवां साल है जिसे 2003 में डॉ. जितेंद्र रघुवंशी ने प्रारंभ किया तब से इसका आयोजन अनवरत चल रहा है।

कार्यक्रम में पार्टी का प्रतिनिधित्व जिला मंत्री पूरन सिंह जी किया व संचालन रंगकर्मी डॉ. विजय शर्मा ने किया।

उपस्थित गणमान्य लोगों में श्रीमती भावना जितेंद्र रघुवंशी, सरला जैन, भाकपा राज्य परिषद सदस्य ओमप्रकाश, ताराचंद, तेज सिंह वर्मा, जगदीश प्रसाद, निरोती लाल, पूरन चंद्र राजपूत, भीकम सिंह, पूरन सिंह यादव, जगदीश शर्मा, डॉ. रमेश चंद्र शर्मा, डॉ. श्री भगवान शर्मा, डॉ. सुनील शर्मा, शिरोज से आशीष मिश्रा, रामभरत उपाध्याय नीरज मिश्रा, अमीर अहमद साब, रमेश पंडित, नीतू दीक्षित, भारत सिंह, अनिल शर्मा, डॉ. आनंद राय, एम पी दीक्षित आदि उपस्थित थे

'पश्चिमी ज्ञान' को 'भारतीय ज्ञान' से बदलने से...

पेज 5 से जारी...

लेखन और बोली दोनों थी, और यह भारतीय इतिहास में सदियों तक जारी रहा। जब इस देश में प्रिंट प्रौद्योगिकी आई, तो यह हर उस भाषा के लिए उपलब्ध नहीं थी, जिसमें व्यापक साहित्य था, न ही यह उन सभी भाषाओं तक पहुंच सकी, जिसके बहुसंख्यक वक्ता थे। प्रिंट प्रौद्योगिकी केवल उन समुदायों तक पहुँच सकी जिस समुदाय से लोग नौकरशाही में लिए जा सकते था या ईस्ट इंडिया कंपनी के सरकारी कालेजों में काम करने के लिए आते थे।

भारत में मुद्रण के लिए भाषाओं का चयन उनकी साहित्यिक क्षमताओं या उनकी प्राचीनता के आधार पर नहीं, बल्कि उनके मुनाफों के आधार पर किया गया था। इस प्रकार, मौखिक और लिखित प्रस्तुति वाली ज्ञान की परंपराएं उन ज्ञान परंपराओं से कटी रही जो ज्ञान परम्पराएं केवल मौखिक थी। नतीजतन, वे सामाजिक वर्ग जिनके पास लिपि और वे सामाजिक वर्ग जो लिपि से वंचित थे उनके बीच विभाजन भारत के मध्यकाल से आधुनिकता के संक्रमण के महत्वपूर्ण समय बढ़ गया था। उन सामाजिक वर्गों के बीच विभाजन, जिनके पास पत्रों तक आसान पहुंच थी और जिन्हें इस बात से वंचित रखा गया था कि पहुंच में आसानी मध्यकालीन समय से आधुनिकता की ओर भारत के परिवर्तन के उस महत्वपूर्ण क्षण में बढ़ गई थी।

इस प्रकार, "सभी भारतीय ज्ञान" "सभी स्मृति" के साथ मजबूती से बंधी एक एकल और एकीकृत प्रतीकात्मक ग्रिड की मदद से भारतीय परंपराओं में ज्ञात सब कुछ को वर्गीकृत करने की एक भव्य योजना को तैयार करने की भारत की संभावना, उस तरह से व्यवहार्य संभावना नहीं बन सकी जैसा कि एक सदी पहले यूरोप में संभव हुआ था।

जिस समय भारतीय लोग अपने घरों के निर्माण में लगे हुए थे, उस समय वास्तुकला 'वर्नाक्यूलर' (देशज) और 'आर्किटेक्चर' में विभाजित हो गई थी। 'भाषा' के रूप में बोली जाने वाली भाषाओं को "भाषाओं" और "बोलियों" के रूप में अलग–अलग सूचीबद्ध किया गया। गहरे विभाजित "स्मृति क्षेत्र" के घावों के साथ भारत पिछली दो सदी से "सार्वभौमिक ज्ञान" के विचार को आत्मसात करने की कोशिश कर रहा है।

अब यदि कोई विचारधारा इस फतासी को पोषित करती है कि ''समस्त ज्ञान' प्राचीन भारत में विकसित हुआ था और यह विचाराघात 'पश्चिमी ज्ञान' को बदलने के लिए ''भारतीय ज्ञान'' लाने के लिए शिक्षकों को बाध्य करती है, तो जाहिर है कि यह इतिहास में ज्ञात सबसे बड़ी आपदा होगी। यह छात्रों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर सकती है जो कि पश्चिमी ज्ञान प्रणाली में सब कुछ को घृणा की वस्तु समझेगी।

यह उस भयानक सामाजिक विभाजन की उपस्थिति को भी नकार सकता है जिसने अधिकांश जातियों और सभी महिलाओं को ज्ञान के दायरे से वंचित रखा है। सबसे बुरी बात है कि भारत को अतीत की ओर ले जाने की कोशिश भारत को अज्ञानता का महाद्वीप बना देगी।

मुक्ति संघर्ष पढ़िए

चन्दे की दरः

वार्षिक	: 350 रूपये
अर्द्धवार्षिक	: 175 रूपये
एक प्रति	: 7 रूपये
एजेंसी डिपोजिट	
प्रति कापी :	70 रूपये

खाता नामः **मुक्ति संघर्ष साप्ताहिक**
बैंकः **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रेस एरिया ब्रांच**
चालू खाता संख्याः **1033004704**
आईएफसी कोडः **सीबीआईएन0280306**

कापी मगाने के लिये लिखेंः
व्यवस्थापकः मुक्ति संघर्ष साप्ताहिक
अजय भवन, 15–का. इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग
नयी दिल्ली–110002

नोटः डीडी और चेक केवल ''मुक्ति संघर्ष साप्ताहिक'' के नाम होना चाहिए।

पी.पी.एच. पब्लिकेशन

पुस्तक	लेखक	मूल्य
1. भारतीय दर्शन में क्या जीवंत है और क्या मृत	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	500.00
2. बाल जीवनी माला	कॉपरर्निकस	12.00
3. बाल जीवनी माला	निराला	12.00
4. बाल जीवनी माला	रामानुज	12.00
5. बाल जीवनी माला	मेंडलिफ	50.00
6. बाल जीवनी माला	प्रेमचंद	50.00
7. बाल जीवनी माला	सी.वी. रमन	50.00
8. बाल जीवनी माला	आइजक न्यूटन	50.00
9. बाल जीवनी माला	लुईपाश्चर	50.00
10. बाल जीवनी माला	जगदीश चन्द्र बसु	50.00
11. फैज अहमद फैज–शख्स और शायर	शकील सिद्दीकी	80.00
12. फांसी के तख्ते से	जूलियस फ्यूचिक	100.00
13. कितने दोबाटिक सिंह भारत विभाजन की दस कहानियां	भूमिकाः भीष्म साहनी	60.00
14. मार्क्सवाद क्या है?	एमिल बर्न्स	40.00
15. फैज़ अहमद फ़ैज़ः प्रतिनिधि कविताएं	संप श्री अली जावेद	60.00
16. दर्शन की दरिद्रता	कार्ल मार्क्स	125.00
17. हिन्दू पहचान की खोज	डी.एन. झा	100.00
18. प्राचीन भारत में भौतिकवाद	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	200.00
19. 'जब मैंने जाति छिपायी थी' तथा अन्य कहानियां	बाबुराव बागुल	200.00
20. बाल–हृदय की गहराइयां माँ–बाप और शिक्षकों से अंतरंग बातचीत	वसीली सुखोम्लीन्स्की	350.00
21. चीन की पुरस्कृत कहानियां भाग–1, 2		185.00
22. बच्चों सुनो कहानी	लेव तोलस्तोय	175.00
23. जहां चाह वहां राह–उज़बेक लोक कथाएं		360.00
24. हीरेमोती–सोवियत भूमि की जातियों की लीक कथाएं		300.00
25. दास्तान–ए–नसरूदीन	लियोनिद सोलोवयेव	370.00
26. लेनिन–क्रुप्स्काया (संस्मरण)	क्रुप्स्काया	485.00
27. साम्राज्यवाद, पूंजीवाद की चरम अवस्था	लेनिन	65.00
28. बिसात–ए–रक्स	मख़दूम	100.00
29. भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण	भगवत शरण उपाध्याय	100.00
30. राहुल निबंधावली (साहित्य)	राहुल सांकृत्यायन	90.00
31. मैं नास्तिक क्यों हूं	भगत सिंह	75.00
32. विवेकानंद सामाजिक–राजनीतिक विचार	विनोय के. राय	75.00
33. रामराज्य और मार्क्सवाद	राहुल सांकृत्यायन	60.00
34. कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र	मार्क्स एंगेल्स	50.00
35. भगत सिंह की राह पर	ए.बी. बर्धन	15.00
36. माटी का लाल–कृति पुरूष कामरेड दुर्जन भाई	डा. रामचन्द्र	110.00
37. क्या करें	लेनिन	80.00
38. मेक इन इंडिया –आंखों में धूल	सी. मुरलीधर, एम. सत्यानन्द	30.00
39. भारतीय इतिहास में जाति और मुद्रा	इरफान हबीब	40.00
40. वर्ग जाति आरक्षण और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष	ए.बी. बर्धन	60.00

आर्डर भेजें:
पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड
5–ई, रानी झांसी मार्ग
नई दिल्ली–110055
दूरभाषः 011–23523349, 23529823
ईमेलः pph5e1947@gmail.com
https//pphbooks.net

दिल्ली के शोरूम
जी–18, आउटर सर्कल, कनाट प्लेस
नई दिल्ली–110001, फोनः 23324064
पीपीएच बुकशॉप, जेएनयू सेंट्रल लाइब्रेरी के पास,
नई दिल्ली–110 067, फोनः 65447645
पीपीएच शॉप, अजय भवन
15, कामरेड इन्द्रजीत गुप्त मार्ग, नई दिल्ली–2

नोटः आप भेज सकते हैंः
चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रानिक मनिआर्डर ''पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड'' के पक्ष में
बैंक विवरणः
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंटः 32074674284, आई.एफ.सी. कोडः SBIN0009371

लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, देश ...

पेज 1 से जारी...

सार्वजनिक क्षेत्र के वे वित्तीय संस्थान जिनका अडानी कंपनियों में निवेश था उनका हालत अच्छी नहीं है। एलआईसी का लगभग 30,000 करोड़, भारतीय स्टेट बैंक का 42,000 करोड़ और इसी तरह से प्रदीप शिपिंग कंपनी, गैल, आईओसी के अलावा अन्य कई सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अडानी कंपनियों में निवेश करना पड़ा था, और यह साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने मददकर्ता की भूमिका निभाई है। यह जगजाहिर है कि प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रूचि लेते हुए अडानी कंपनियों को विदेशों में कारोबार फैलाने के लिए प्रोत्साहन दिया।

ऑस्ट्रेलिया की खदानों के लिए भारत सरकार ने अडानी कंपनी की गारंटी ली और उसे लिए धन का इंतजाम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से कराया गया था। अडानी की मोरिसस की कंपनी को गृहमंत्री ने सुरक्षा दी। अडानी ग्रुप को इजरायल में पोर्ट के लिए भारत सरकार ने उसकी संप्रभुत्व गारंटी दी। विद्युत संयंत्र अनुबंध के मामले में श्रीलंका से एक नई कहानी मिल सकती है।

यह कुत्सित सच्चाई अच्छे से बयान करती है कि लोगों की जिन्दगी में असमानताएं क्यों घृणित स्तर तक बढ़ रही हैं।

ऑक्सफैम इंडिया की 16 जनवरी 2023 को असमानता पर जारी की गई रिपोर्ट में पाया गया कि मात्र पांच प्रतिशत भारतीय देश की 60 प्रतिशत संपत्ति के मालिक हैं जबकि आबादी के निचले पचास प्रतिशत के पास केवल तीन प्रतिशत संपत्ति है। यहां यह जिक्र करना जरूरी है कि पिछले साल 2021 में आबादी का इस पचास प्रतिशत के पास 13 प्रतिशत संपत्ति थी। आबादी का ऊपरी एक प्रतिशत हिस्सा जो कि 2021 में कुल संपत्ति का 22 प्रतिशत का मालिक था उसकी संपत्ति 2022 में बढ़कार 40.3 प्रतिशत हो गई। रिपोर्ट में कहा गया कि यदि भारत के अरबपतियों की समस्त संपत्ति पर दो प्रतिशत कर लगाया जाए तो इससे देश में कुपोषितों के पोषण के लिए अगले तीन साल के लिए जरूरी 40,423 करोड़ रु. की सहायता मिलेगी। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि भारत सरकार के वकील ने सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल एक शपथपत्र में कहा था कि पांच साल से कम के 65 प्रतिशत बच्चों की मृत्यु का कारण कुपोषण है। देश के भूख सूचकांक और भी खराब हो गया है और 122 देशों में से भारत का स्थान 107वें नंबर पर है। दिहाड़ी मजदूर अत्याधिक कठिनाई में हैं। इस साल की क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल की 25 प्रतिशत आत्महत्याएं दिहाड़ी मजदूरों की थी।

''सर्वाइवल ऑफ द रिचस्टः द इंडिया स्टोरी'' रिपोर्ट भी कहती है कि 2012 और 2021 में भारत में सृजित 40 प्रतिशत संपत्ति आबादी के मात्र एक प्रतिशत के पास गई और केवल 3 प्रतिशत संपत्ति आबादी के निचले पचास प्रतिशत के पास पहुंची, रिपोर्ट में आगे कहा गया कि भारत में अरबपतियों की कुल संख्या 2020 में 102 थी जो कि 2022 में बढ़कर 166 हो गई है।

भारत के 100 सबसे बड़े अमीरों की संयुक्त संपत्ति 54.12 लाख करोड़ रुपये पहुंच गई है–यह राशि इतनी बड़ी है कि यह 18 महीनों तक भारत सरकार के पूरे बजट का भार उठा सकती है।

कोविड महामारी से पहले 2019 में केंद्रीय सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स स्लैब को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया, जिन कॉरपोरेट कंपनियों में नई कंपनियां मिलाई गई वे 15 प्रतिशत टैक्स दे रहे हैं। इस नई टैक्सेशन (कर नीति) से 1.89 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर जीएसटी अैर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की नीति अपनाई जबकि साथ ही साथ छूट में कटौती जारी रही। ग्रामीण और शहरी महंगाई में फर्क बढ़ गया है।

सरकार अमीर लोगों और कॉरपोरेट कंपनियों पर टैक्स लगाने की बजाय बाकी आबादी पर अधिक टैक्स लगा रही है क्योंकि गरीब जनता अपनी आय का एक बड़ा हिस्से पर टैक्स देते है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि ''देश भर में आबादी के निचले पचास प्रतिशत अपनी आय के प्रतिशत के रूप में ऊपर आय वाले दस प्रतिशत की तुलना में छह गुना अधिक अप्रत्यक्ष कर देते हैं।

इनइक्विलटी रिपोर्ट साफ शब्दों में स्पष्ट करती है कि भाजपा–आरएसएस मोदी सरकार की नीतियां खुल्लम–खुल्ला कॉरपोरेटों को प्रोत्साहन दे रही है उनमें भी विशेष प्रोत्साहन प्रधानमंत्री के दो मित्रों को। इसी को ही क्रोनी पूंजीवाद बनाना कहा गया है।

कोरोना महामारी की स्थिति को दुनिया भर में कई सरकारों ने कानूनों में बदलाव किया था। विपक्ष को और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन को दबाने के लिए कानूनों में ये बदलाव जनता की दुर्दशा पर कॉरपोरेट कंपनियों को मुनाफा बढ़ाने में मदद कर रहे थे। इससे आर्थिक संकट और बढ़ती असमानता की गति बढ़ा दी है।

यूरोप में चल रहे युद्ध स्थिति ने अर्थव्यवस्था के बढ़ते संकट को बढ़ा दिया है। एक और रूस के यूक्रेन के साथ युद्ध में हथियार लॉबी यूक्रेन को अपना मोहरा बनाकर अमरीका–नाटो को रूस के साथ परोक्ष युद्ध की ओर धकेल रही है, दूसरी ओर साम्राज्यवादी लॉबी साथ ही साथ युद्ध टकराहटों को एशिया में लाने की कोशिश में है। कामगार जनता के कष्टों के दम पर जंगखोर लॉबी अपने सुखद स्थलों में हैं। इससे युद्धग्रस्त देशों की कामगार जनता की मुसीबतें रूस और यूक्रेन में बढ़ गई हैं लेकिन यह कई दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर हानिकर प्रभाव का भी कारण है।

मंदी और आर्थिक संकट की वैश्विक स्थिति पर पूंजीवादी समर्थक देशों ने प्रतिक्रिया जताते हुए सामाजिक सुरक्षा, पेंशन व्यवस्था, नौकरी और वेतन सुरक्षा पर हमले बढ़ा दिए हैं। इसके विरोध में ट्रेड यूनियनों और समाज के दूसरे तबकों ने भीषण प्रदर्शन किए हैं। हम हाल में यदि कुछ देशों का नाम ले तो फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीस, स्पेन, अमरीका और आस्ट्रेलिया में आंदोलन चल रहे हैं। सरकार यूनियनों पर नियंत्रण रखने के लिए दमन का सहारा ले रही है और कानूनों में बदलाव कर रही है।

श्रम कानूनों में प्रतिगामी बदलावों और उनके संहिताकरण करने के कारण हम अपने देश में पहले ही सरकार के हमले में हैं जिसका हम ट्रेड यूनियनों के संयुक्त प्लेटफॉर्म के माध्यम से संयुक्त रूप से विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने केंद्र में और जिन राज्यों में उनकी सरकार हैं या उनकी गठबंधन सरकार है वहां कानून बना दिए है। केंद्रीय शासित प्रदेशों में वे केंद्र कानूनों को थोप रहे हैं। यूनियनों की राज्य इकाइयों को इन कानूनों को बनाने से रोकने, या फिर जिन राज्यों में ये कानून बन गए है उन्हें सूचित करने या लागू होने से रोकने के लिए बड़े प्रतिरोध खड़े करने होंगे।

प्रधानमंत्री कार्यालय सीधे हस्तक्षेप कर श्रम मंत्रालय, राज्य सरकारों को दरकिनार करते हुए कानूनों में बदलाव के निर्देश दे रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेटों की वे मांगे पूरी हो सकें जो कि निवेश के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ सीधी बातचीत के दौरान शर्त के रूप में रखी गई थी। यह तथ्य अभी हाल में कर्नाटक राज्य में विधायी संशोधन विधेयक के माध्यम से फैक्टरी कानून में बदलाव करने में सामने आया। यूनियनों ने राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह के शहादत दिवस 23 मार्च को इसके खिलाफ सफलतापूर्वक हड़ताल की थी। हमें अभी समाचार मिला कि तमिलनाडु में भी इसी तरह के विधेयक को पेश किया गया है।

सभी अपेक्षाओं पर असफल होने के बाद सत्ताधारी पार्टी ''हिन्दू राष्ट्र'' के नारे पर और ज्यादा जोर से बोलते हुए नफरत की राजनीति और सांप्रदायिक बंटवारे पर टिकी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान कि हिन्दू हजार साल के बाद जागे हैं सूचित करता है कि सांप्रदायिक कट्टरपंथी अपनी कार्यवाहियों में उत्साही हो गए हैं।

सांप्रदायिक रूप से प्रेरित हिंसक समूहों को प्रोत्साहन मिल रहा है। इस संबधं में हरियाणा से भयावह जानकारी मिल रही है कि इस तरह के दलों को गऊ रक्षक दल के नाम पर चौकसी करने को पुलिस अनुमति दे रही हैं यह एक उदाहरण है कि राज्य तंत्र व्यक्तियों को व्यैक्तिक स्तर पर कानून को अपने हाथ में लेने की अनुमति दे रहा है।

हाल में रामनवमी के दिन की सांप्रदायिक हिंसाएं पर्याप्त सूचक हैं कि यदि सरकार धार्मिक गतिविधियों के नाम पर इन समूहों को प्रश्रय देती रहेगी तो भविष्य में इस तरह की घटनाएं होंगी।

पाठ्यक्रम में जरूरी बदलाव के नाम पर शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिगामी दृष्टिकोण इसे आक्रामक प्रयासों को बनाने के लिए है ताकि अगली पीढ़ी को सच्चाई से दूर रखा जाए। तब इन ताकतों को भावनात्मक मुद्दों पर मिथ फैलाने और सांप्रदायिक दंगों के लिए ज्यादा आसानी होगी ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमले हो रहे हैं इनसे विकास की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने वाले आर्थिक स्तंभ कमजोर होंगे और इसके अलावा युवाओं के लिए बेहतर रोजगार के संबंध में यह प्रतिगामी होगा।

सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग काफी बढ़ गया है ओर ईडी, सीबीआई, यूएपीए आदि आम बात हैं, विपक्षियों की आवाज दबाने के लिए। राहुल गांधी का मामला विशिष्ट रूप से सरकार की चालों को बताता है कि गुजरात की निचली अदालत के फैसले के तुरंत बाद किस तरह से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को खारिज कर दिया। सरकारी संस्थानों को, भारतीय संविधान के खिलाफ सत्ताधारी पार्टी की नीतियों पर चलने के लिए साधा जा रहा है। संसदीय जनतंत्र का मजाक उड़ाने की यह गति स्पष्ट थी जब सत्तापक्ष संसद को नहीं चलने दे रहा था।

सीलबंद लिफाफों में न्यायालयों को सूचना देने की व्यवस्था सरकार द्वारा अपनाई गई थी मीडिया के साथ–साथ उन नागरिकों का मुंह बंद करने के लिए जिनसे सरकार नाखुश है। 5 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश ने अन्य जजों के साथ इस प्रक्रिया को प्राकृतिक न्याय के खिलाफ कहते हुए इसे खत्म करने का आदेश दिया।

सत्ताधारी दल की ओर से संविधान पर हमला सभी जानते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि किस तरह भारत के उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ और कानून मंत्री रिजिजू बार–बार अपने वक्तव्यों से संविधान को पलटने की कोशिश कर रहे हैं।

भारत में ट्रेड यूनियनें स्थानीय और औपनिवेशिक शासकों के दमन और उत्पीड़न के खिलाफ भारतीय जनगण के जनतांत्रिक उभार से विकसित हुई है, ट्रेड यूनियन, मजदूरों के अधिकारों के वर्तमान और भविष्य के लिए लड़ने का संगठन है और जनतंत्र का मूल तत्व है।

एटक ने यूनियन में संगठित होने के अधिकार और सामूहिक समझौतों का अधिकार, जनतंत्र के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और विरोध के अधिकारों को स्थापित कराने में अपनी भूमिका अदा की है और इन अधिकारों को भारतीय संविधान में जगह मिली। इन अधिकारों पर अलग–अलग भेषों में हमले हो रहे हैं।

मजदूर वर्ग का यह सर्वोच्च कर्तव्य है कि वह इन अधिकारों को अपने लिए और पूरे समाज के लिए सुरक्षित करे।

हम 30 जनवरी को वर्कर्स के राष्ट्रीय कन्वेंशन के लिए गए निर्णयों को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, आरएसएस–भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ और मजदूर–विरोधी, किसान विरोधी, जन–विरोधी, राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए कन्वेंशन के संदेश से हमारी प्रतिबद्धता है, हम कन्वेंशन के संदेश को देश के कोने–कोने तक ले जाएंगे, सरकार का असली चेहरा जनता को दिखाएंगे ताकि जनता निष्ठुर निरंकुश सरकार की रवानगी का आदेश देने का निर्णय ले सके।

मई दिवस जिंदाबाद

दुनिया के मजदूरों एक हो।

मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक 30 अप्रैल– 6 मई, 2023

Delhi Postal Regd. No. DL(C)-01/1277/2021-23
Licenced to Post without Pre-payment. U(C)-102/2021-23
(R.N.I. No. 20196/70) Posted in LPC, DRMS, Friday & Saturday

प्रकाशन तिथि: 28.4.2023

लेनिन आज तक भी राह दिखा रहे हैं

नई दिल्ली: 22 अप्रैल महान कामरेड वी. आई. लेनिन का जन्मदिन समारोह लेनिन मूर्ति नेहरू पार्क दिल्ली में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दिल्ली राज्य परिषद द्वारा आयोजित किया गया।

भाकपा महासचिव डी राजा महासचिव, दिल्ली भाकपा राज्य सचिव प्रो. दिनेश वार्ष्णेय, भाकपा राष्ट्रीय सचिव रामाकृष्णा पांडा ने लेनिन की मूर्ति को माला पहनाकर एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की।

राजा ने संबोधित करते हुए कहा कि महान लेनिन ने ही विश्व की प्रथम क्रांति की। इसी महान अक्टूबर क्रांति ने ना सिर्फ सर्वहारा की सरकार बनाई बल्कि पूरे विश्व के पूंजीपति वर्ग के शोषण को विचारधारात्मक चुनौती दी साथ ही विश्व में साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष को मंजिल तक ले जाने का रास्ता दिखाया।

भाकपा राज्य सचिव दिनेश वार्ष्णेय ने महान लेनिन को क्रान्तिकारी आन्दोलन का नेतृत्व करने वाला बताया और कहा कि लेनिन ने विश्व सर्वहारा व कामगार जनता को संघर्ष का रास्ता दिखाया।

इस आयोजन में भाकपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य शंकरलाल, महेश राठी, वी. एस. गिरी, साथी सतीश, मुकेश कश्यप, राजेश कश्यप, विनोद एटक दिल्ली नेता, साथी केहर सिंह, एआईवायएफ महासचिव तिरूमलई रमन, शशि कुमार, संजीव कुमार राणा, राजकुमार, बबन कुमार सिंह ने भी अन्य साथियों सहित लेनिन को पुष्प अर्पित किये।

पश्चिमी बंगाल

रूसी क्रांति के जनक व्लादिमीर इलिच लेनिन की 154वीं जयंती 22 अप्रैल शनिवार को कोलकाता समेत पूरे राज्य में मनाई गई।

इस दिन को सभी जिलों के विभिन्न पार्टी कार्यालयों में उचित सम्मान के साथ मनाया गया। दफ्तरों को लाल झंडों और लाल बत्तियों से सजाया गया। जिलों के कुछ स्थानों पर सभाएं भी हुई।

प्रदेश पार्टी कार्यालय भूपेश भवन में सम्मान पूर्वक इस दिन को मनाया गया। पार्टी के प्रदेश सचिव स्वपन बनर्जी ने लेनिन के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। माल्यार्पण के बाद एक संक्षिप्त भाषण में उन्होंने कहा कि देश और राज्य की वर्तमान स्थिति में लेनिन द्वारा दिखाया गया मार्ग ही मेहनतकश लोगों के जीवित वातावरण को वापस ला सकता है। लेनिनवाद एक ऐसी मशाल है जो हमें केंद्र में साम्प्रदायिक और कारपोरेटपरस्त शासक और राज्य में निरंकुश शासक को हराने का असली रास्ता दिखाएगी। विश्व की पहली क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। उस महान अक्टूबर क्रान्ति ने विश्व के शोषकों को न केवल सैद्धान्तिक चुनौती दी, साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी लड़ाई आज भी जारी है। लेनिन को श्रद्धांजलि देने और लेनिन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए भूपेश भवन में उपस्थित अन्य लोगों में तपन गांगुली, कल्याण बनर्जी और गौतम रे सभी राज्य सचिवमंडल सदस्य, अमिताभ चक्रवर्ती, महासचिव, आईपीसीए, सुवम बनर्जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष एआईएसएफ, अरुण चट्टोराज, राज्य सचिवालय सदस्य, एटक, तापस त्रिपाठी, जुक्ता समिति, राज्य परिषद सदस्य संजय दास और निहार घोष और भूपेश भवन के कर्मचारी शामिल थे।

कोलकाता में मुख्य कार्यक्रम एस्प्लेनेड में लेनिन की प्रतिमा के नीचे आयोजित किया गया था। यहां इस्कफ और स्टेट लेफ्ट फ्रंट की पहल पर इस दिन को औपचारिक रूप से0 पूरे सम्मान के साथ मनाया गया।

पिछले वर्षो की तरह इस्कफ द्वारा आयोजित यह एक छोटी बैठक थी। इस्कफ के नेताओं ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस्कफ के प्रदेश अध्यक्ष भानुदेव दत्ता ने कहा कि लेनिन के बताए रास्ते ही आज भी मेहनतकशों को जीने की राह दिखाने का एक मात्र रास्ता हैं।

बाद में, राज्य वाम मोर्चा द्वारा इस दिन को उचित सम्मान के साथ लेकिन सरल तरीके से मनाया गया। वाममोर्चा के अध्यक्ष विमान बसु, भाकपा राज्य सचिव स्वपन बनर्जी, प्रबीर देव, तपन गांगुली, गौतम राय, भाकपा के संजय दास, माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम, माकपा के राज्य सचिव सूर्यकांत मिश्रा, मनोज भट्टाचार्य, आरएसपी, नरेन चटर्जी, एफबी, अन्य वाम दलों के नेताओं और विभिन्न जन संगठनों ने भी लेनिन की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से डी. राजा द्वारा BFL Infotech Ltd. (Media Division), C-9, Sector-3, Noida, Dist. Gautam Budh Nagar, UP द्वारा मुद्रित, अजय भवन, 15–कामरेड इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली–110 002 से प्रकाशित। **संपादक**: रणबीर सिंह यादव फोन: 011–2323 0762 फैक्स 91–011–2323 5543.
e-mail: newagemukti@gmail.com, Layout: Udai Bhan Rajbhar.